✳Website : www.kalamlok.com✳

वर्ष - 10 अंक - 181

बक्सर, रविवार 01 नवम्बर 2026



◄ 7|

कलम लोक

| पृष्ठ - 8

मूल्य 2 रू.

"हमारे सुख–दुःख का कारण दूसरे व्यक्ति या परिस्थितियाँ नहीं अपितु हमारे अच्छे या बुरे विचार होते हैं।

रामलीला मैदान रैली

250 कैमरे और 3,500 जवान रखेंगे नजर, सुरक्षा के सख्त इंतजाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित की जाएगी। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगभग 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से कार्यक्रम स्थल की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी।



दिल्ली पुलिस के अनुसार, रैली के दौरान भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। यहां कैमरों से प्राप्त सीधी तस्वीरों की निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय स्थिति की जानकारी तत्काल मिल सके और समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा पुलिसकर्मी शरीर पर लगाए जाने वाले कैमरों का इस्तेमाल करेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से लैस कैमरों की मदद से मैदान के भीतर और आसपास चेहरों की पहचान और निगरानी की व्यवस्था भी की गई है।

सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पूरे रामलीला मैदान को 14 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र की जिम्मेदारी सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। इन 14 क्षेत्रों को आठ क्षेत्रीय समूहों में बांटा जाएगा, जिनकी निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेंगे। मैदान के भीतर और आसपास केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों सहित लगभग 3,500 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी। पुलिस का अनुमान है कि इस रैली में करीब 50 हजार लोग शामिल हो सकते हैं।

रामलीला मैदान में प्रवेश और निकास के लिए कुल आठ द्वार निर्धारित किए गए हैं। इनमें से आम लोगों को केवल तीन द्वारों से प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि शेष द्वार अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आवागमन के लिए आरक्षित रहेंगे। मैदान में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की दो चरणों में तलाशी ली जाएगी। इसके लिए सुरक्षा जांच उपकरण, धातु पहचानने वाले यंत्र और अवरोधक लगाए जा रहे हैं। मैदान के चारों ओर भी पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी। पुलिस ने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेष निकासी व्यवस्था भी तैयार की है। इसके तहत लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अलग द्वार बनाया गया है। भीड़ की आवाजाही पर लगातार नजर रखी जाएगी, ताकि कार्यक्रम स्थल पर अनावश्यक भीड़ जमा न हो और लोगों का आवागमन व्यवस्थित बना रहे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भीड़ के कारण शहर के अन्य हिस्सों में यातायात और सामान्य गतिविधियां प्रभावित न हों।

दिल्ली पुलिस ने रैली के आयोजकों को पेयजल, महिलाओं के लिए अलग शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

वाहनों की पार्किंग और यातायात प्रबंधन को लेकर यातायात पुलिस के साथ समन्वय बनाने को भी कहा गया है। इसके अलावा रैली में शामिल होने के लिए आने वाली बसों की संख्या और उनके आवागमन से संबंधित जानकारी भी मांगी गई है, ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारु रखा जा सके। पुलिस का प्रयास है कि बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बावजूद रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक न हो।

ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी

मोदी-शाह से भी निपट लेंगे, लेकिन उनका हथियार पहला टारगेट

नई दिल्ली (एजेंसी)।



राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी शाह से तो निपट लेंगे, लेकिन पहले उनके छोड़े गए हथियार ज्ञानेश कुमार को निपटा दें। इंडिया गठबंधन के सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम में, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और शाह शायद टॉप पर हैं। हम उनसे निपटेंगे, लेकिन आप उनके औजार हैं, और इसलिए आप हमारा पहला टारगेट हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार सोचते हैं, या उनके नीचे पांच या सात लोग सोचते हैं कि बेदाग रहने से वो बच जाएंगे तो मैं उन्हें प्यार और स्नेह के साथ यह सुझाव देना चाहूंगा कि देश में क्या हो रहा है, उस पर एक नजर डालें।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम आपको भागने नहीं देंगे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने भारत पर यह हमला किया है। ज्ञानेश कुमार सिर्फ एक हिस्सा हैं और भी कई लोग हैं। हमें पता है कि वे कौन हैं। हम गहराई से समझते हैं कि वह कौन हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह आपके लिए एक चेतावनी है। चीजें बदल रही हैं। कृपया इस चेतावनी को सुनें और समझें कि यह एक नया राजनीतिक हथियार है, जो बाग में बैठा है और अगर आप अपनी राह पर चलते रहे तो यह हथियार आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा।

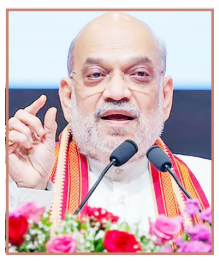
राहुल गांधी ने कहा कि मैं यह प्यार और स्नेह के साथ कह रहा हूं। हम बुरे या दुष्ट लोग नहीं हैं, लेकिन हम संविधान और हमारी जनता की आवाज़ की रक्षा करेंगे। मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं कि ज्ञानेश कुमार का महाभियोग ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें राजद्रोह के लिए कोर्ट में भी ट्रायल होना चाहिए ताकि न्याय मिल सके।

बस एक छोटी सी बात कहनी है

राहुल गांधी ने कहा कि मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 13.3 करोड़ वोटर हटा दिए गए। यह हर सातवें भारतीय में से एक है। भारत के 15 फीसदी वोटर हटा दिए गए है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में, इन वोटरों ने कथित तौर पर वोट किया। विपक्ष और विजेताओं के बीच फर्क सिर्फ 3 फीसदी वोट का था। यानी यह चुनाव 3 फीसदी वोटों से जीता गया। अब खुद चुनाव आयोग कह रहा है कि उन 15 फीसदी वोटरों को कभी वोट नहीं देना चाहिए था। इसका मतलब है कि निर्वाचन आयोग खुद यह कह रहा है कि 2024 की लोकसभा चुनाव अवैध चुनाव है।

सरदार पटेल ने आजादी के बाद सिर्फ 1,218 दिन में वो करके दिखाया, जो सबको असंभव लगता था : अमित शाह

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभभाई पटेल को याद करते हुए कहा कि सरदार साहब का जीवन हर युवा के लिए त्याग और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा है।



अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल वह महान व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने न केवल देश के इतिहास को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्र भारत की भौगोलिक एकता को भी मजबूत आधार प्रदान किया।

उन्होंने विभिन्न रियासतों और राज्यों का एकीकरण कर देश को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया। आज भारत का जो अखंड स्वरूप हमारे सामने है, उसके निर्माता सरदार पटेल थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत के भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण के लिए न केवल सफल प्रयास किया, बल्कि भारत को एक सूत्र में पिरोया। एक समय था, जब हमें आजादी मिली, तब दुनियाभर के राजनीतिक पंडित कहते थे कि आजादी के बाद भारत बिखर जाएगा, लेकिन सरदार पटेल ने आजादी के बाद सिर्फ 1,218 दिन में वह करके दिखाया, जो सबको असंभव लगता था। उन्होंने एक अखंड भारत की रचना की। आज सरदार पटेल की संकल्पना से बना भारत दुनिया के सामने गौरव के साथ खड़ा है।

अमित शाह ने कहा कि इसी साल 31 मार्च को देश नक्सलवाद से मुक्त होकर अब नशामुक्त देश की दिशा में आगे बढ़ गया है। आज सरदार पटेल की 151वीं जयंती पर मैं देशभर के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमने जो लक्ष्य रखा है, 31 दिसंबर 2029 तक देश को संपूर्ण रूप से नशे से मुक्त करने का, उसे पूरा करें। प्रधानमंत्री ने जो विकसित भारत की कल्पना की है, उसका पहला चरण नशामुक्त भारत है।

राहुल गांधी को जीवनभर अपना 'मॉक प्रधानमंत्री' बनाए रखें; विपक्ष पर भाजपा का तंज



नई दिल्ली (एजेंसी)।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ 'इंडिया' गठबंधन के प्रतीकात्मक जन महाभियोग को लेकर शनिवार को भाजपा ने विपक्ष पर संसद का उपहास करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को चाहे कितनी भी बार लॉन्च करने की कोशिश कर ले, वह सफल नहीं होगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, ''आप 'प्रतीकात्मक संसद' (मॉक पार्लियामेंट) आयोजित करें या मार्च निकाल लें, दुनिया समझ चुकी है कि राहुल गांधी के पास आगे बढ़ने के लिए कोई ईंधन ही नहीं है। यह 'सैटेलाइट' कभी लॉन्च नहीं होने वाला।''

उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे तो राहुल गांधी को जीवन भर के लिए एक ''मॉक प्रधानमंत्री'' बनाकर रख सकता है। यहां भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और निर्वाचन आयोग की कार्यशैली को लेकर झूठ फैला रही है। भाजपा नेता ने कांग्रेस के 'वोट चोरी' वाले आरोपों को 'झूठ' करार दिया और दावा किया, ''हिंदुस्तान में पहली वोट चोरी नेहरू जी ने की थी। नेहरू जी ने सरदार वल्लभभाई पटेल जी के समर्थन को दरकिनार कर उन्हें उनके अधिकार से वंचित किया और लोकतांत्रिक परंपराओं की अनदेखी करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री बने थे।''

पात्रा ने कहा कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन ''आज एक मॉक पार्लियामेंट आयोजित करके लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है।'' पात्रा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, ''आपने जो यह मॉक संसद बनाई है, कृपया इसे खत्म न करें। बस राहुल गांधी को सत्ता पक्ष की ओर बिठा दें। टी-शर्ट हटाकर उन्हें 'कुर्ता-पायजामा' पहना दें और उन्हें वहीं बैठने दें, जबकि आप लोग रोज़ाना किसी 'भजन-कीर्तन' की तरह 'प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री' का जाप करते रहें। उन्हें जीवन भर के लिए अपना 'मॉक प्रधानमंत्री' बनाए रखें। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है।'' इससे पहले, भाजपा ने कहा कि विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट ने विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन की प्रतीकात्मक संसद (मॉक पार्लियामेंट) को मजाक का पात्र बना दिया, और कांग्रेस से पूछा कि वह कब तक फसाने में फंसी रहेगी तथा राहुल गांधी को खुश करने के लिए अपने सियासी जनाजे की सजावट करती रहेगी। सत्तारूढ़ दल की ओर से विपक्षी कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर यह हमला, 'इंडिया' गठबंधन द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाये जाने वाले जन महाभियोग से ठीक पहले आया। यह कार्यक्रम यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर आयोजित किया जा रहा है।

'प्रतीकात्मक संसद को मजाक का पात्र बना दिया'

विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अत्यंत गरीबी की दर 2011 के 27.1 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2023 में 2.6 प्रतिशत पर आ गई है, जिससे अनुमानित 49.60 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा, ''विश्व बैंक के आंकड़ों ने एक तरह से उनके 'प्रतीकात्मक संसद' को मजाक का पात्र बना दिया।''

यूपी को जल्द मिलेगी पहली बुलेट ट्रेन

राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात को 426.71 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन और शिलान्यास

एकतानगर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे के दौरान एकतानगर में 426.71 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन, नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने 307.83 करोड़ रुपये की लागत वाली 23 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 118.88 करोड़ रुपये की आठ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने एकतानगर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन तथा नागरिक सुविधाओं से जुड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

इन परियोजनाओं में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) का होटल, एकता क्रूज, वर्षावन आकर्षण केंद्र, पर्यावरण पर्यटन पथ, मलजल और जल उपचार संयंत्र, चलती सीढ़ियां तथा विद्युत बसें शामिल हैं। इनके माध्यम से एकतानगर को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

एकतानगर रेलवे स्टेशन के पास आईआरसीटीसी की ओर से 127 कमरों वाला आधुनिक होटल बनाया गया है। इस पर करीब 52.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। लगभग दो एकड़ क्षेत्र में विकसित इस होटल में चार श्रेणियों के कमरे, भोजनालय, जलपान गृह, सभागार, सम्मेलन कक्ष और तरणताल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रेलवे स्टेशन के नजदीक होने के कारण रेल मार्ग से आने वाले पर्यटकों को यहां पहुंचने में आसानी होगी। अब तक तीन करोड़ से अधिक पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भ्रमण कर चुके हैं। ऐसे में होटल की नई सुविधा से पर्यटकों को ठहरने का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। इससे पर्यटकों के एकतानगर में अधिक समय बिताने और स्थानीय पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने एकतानगर को पर्यटन की दृष्टि से और आकर्षक बनाने के लिए वर्षावन, एकता और पर्यावरण पर्यटन पथ से जुड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा नर्मदा घाट के उन्नयन और क्षेत्र में भवनों को आकर्षक रोशनी से सजाने की योजना भी शामिल है। इन कार्यों से क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाने के साथ पर्यटकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। मलजल और जल उपचार संयंत्रों के निर्माण से क्षेत्र में स्वच्छता और जल प्रबंधन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने गोरा-भद्र मार्ग के विकास, एकीकृत शून्य अपशिष्ट स्मार्ट ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना और खलवानी पर्यावरण पर्यटन विकास परियोजना की भी आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त कैक्टस उद्यान और तितली उद्यान के एकीकृत विकास की योजना भी शामिल है। गुजरात दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनवीएस-03 उपग्रह को लेकर जीएसएलवी-एफ18 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों और अभियंताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत की स्वदेशी उपग्रह आधारित नौवहन प्रणाली नाविक को और मजबूत करेगा। इससे नौवहन सेवाओं में सुधार होगा और महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

जूता कारखाने में आग लगने से 4 की मौत, 2 गंभीर घायल

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक जूते के कारखाने में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। सूचना मिलते ही दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बचावकर्मियों ने बताया कि सभी 6 लोग कारखाने के भीतर बेहोश अवस्था में मिले थे।

पुलिस ने बताया कि रात 9:32 बजे औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा ने 20 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं। सभी 6 पीड़ितों को तत्काल इलाज के लिए मंगोलपुरी के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 में से 4 को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बाकी 2 का इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर है। दमकल अधिकारी एडीओ पारस कुमार ने कहा, यह जूते बनाने का कारखाना है। यहां जूते बनाए और रखे जाते हैं। आग सबसे पहले तहखाने में लगी।

यूपी को जल्द मिलेगी पहली बुलेट ट्रेन

पीएम मोदी ने उत्तरी कोरिडोर को दी मंजूरी; दिल्ली से काशी का सफर 3.5 घंटे में होगा पूरा

लखनऊ (एजेंसी)।



देश में तीव्र गति रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन के उत्तरी गलियारे को मंजूरी दे दी है। इससे उत्तर प्रदेश को पहली बुलेट ट्रेन मिलने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली से वाराणसी (बनारस) तक की दूरी महज साढ़े तीन घंटे में तय की जा सकेगी। वर्तमान में इस यात्रा में कई घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

इस बीच वाराणसी में गंगा नदी पर प्रस्तावित नए दोहरे तल वाले सेतु को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और बताया कि इस पुल का नाम नमो सेतु होगा। यह पुल रेल और सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के साथ ही वाराणसी तथा आसपास के क्षेत्रों के विकास को नई गति देगा।

गंगा नदी पर बनने वाला नमो सेतु लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना पर करीब 2,657 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और इसे वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह दोहरे तल वाला मिश्रित संरचना का पुल होगा। इसके ऊपरी हिस्से में छह लेन की सड़क बनाई जाएगी, जबकि निचले हिस्से में चार रेल लाइनें विकसित की जाएंगी।

इस पुल के निर्माण से काशी रेलवे स्टेशन की संपर्क सुविधा मजबूत होगी। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर और नमो घाट जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक पहुंचना भी आसान होगा। वाराणसी, बिहार और पूर्वांचल के रेल यात्रियों को इसका विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके बनने से 100 से अधिक अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन का रास्ता खुल सकता है। इससे मौजूदा रेल मार्गों पर दबाव कम होगा और यात्रियों को अधिक रेल सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

नमो सेतु वाराणसी को तीन दिशाओं से बेहतर रेल और सड़क संपर्क उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इससे शहर के भीतर यातायात का दबाव और जाम की समस्या कम होने की भी उम्मीद है। पुल के एक छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिया गया गांव और दूसरे छोर पर नमो घाट स्थित है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर कहा कि कुछ लोग इसे केवल अमीरों के लिए सुविधा बताकर भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सरकार का उद्देश्य किसानों, मध्यम वर्ग और गरीबों सहित सभी वर्गों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण का रास्ता साफ, पीएम मोदी 20 नवंबर को कर सकते हैं शिलान्यास

भागलपुर (संवाददाता)। बिहार के भागलपुर में प्राचीन विक्रमशिला भग्नावशेष परिसर के समीप प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जिला प्रशासन ने परियोजना के लिए 215.355 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करते हुए उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर के भागलपुर दौरे के दौरान इसकी आधारशिला रख सकते हैं।

जिला भू-अर्जन कार्यालय से अधिग्रहीत हुई कुल रैयती जमीन 215.355 एकड़ का ब्योरा शिक्षा विभाग के अधिकृत पदाधिकारी प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद को दखल कब्जा दिला दिया है। शिक्षा विभाग अब इस रिपोर्ट को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजेगा। जिसके बाद बजटीय आवंटन और टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय का निर्माण 219.645 एकड़ में किया जाना है। इसमें 4.290 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है। डीएम अलंकृता पांडे ने कहा है कि जमीन के रैयतों को भुगतान देकर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

परियोजना को लेकर यह जल्दबाजी आगामी 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार यात्रा के मद्देनजर की जा रही है। परियोजना को लेकर पीएमओ ने शिक्षा विभाग से सारी महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। ऐसे



में संभावना है कि 20 नवंबर को प्रधानमंत्री निर्माण परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। बता दें कि यूनिवर्सिटी के निर्माण का नक्शा तैयार हो गया है। यह नक्शा दिल्ली की स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) ने तैयार किया है। नक्शे में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक शैक्षणिक आवश्यकताओं का बेहतरीन समन्वय देखने को मिलेगा। परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के रिसर्च सेंटर, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल लाइब्रेरी और भव्य प्रशासनिक भवन शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने बिहार को दिए पैकेज के तहत नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला को भी एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी।

अंतीचक और मलकपुर मौजा में मिली जमीन

विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए कहलगांव अनुमंडल के अंतीचक में 96.44 एकड़ और मलकपुर मौजा की 95.615 एकड़ रैयती जमीन को अधिग्रहीत किया गया है। अब अंतीचक में सरकारी जमीन के रूप में अनावाद बिहार सरकार की 24.12 एकड़, सर्वसाधारण की 0.19 एकड़ और शिक्षा विभाग की 1.65 एकड़ एवं मलकपुर में अनावाद बिहार सरकार की 1.82 एकड़ और सर्वसाधारण की 0.31 एकड़ जमीन का संबंधित विभाग से राजस्व शाखा द्वारा हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी। जानकारों ने बताया कि रैयती जमीन के मुआवजे के रूप में 84.99 करोड़ रुपये वितरित की गई है।

सोनपुर और अजगैवीनाथ एयरपोर्ट पर बड़े विमानों का होगा मेंटेनेंस, पायलटों को ट्रेनिंग भी मिलेगी

भागलपुर (संवाददाता)। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार दो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पटना के पास सोनपुर और भागलपुर के पास अजगैवीनाथ धाम (सुल्तानगंज) में अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाए जाएंगे। बिहार के विमानन ढांचे को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए दोनों एयरपोर्ट पर बड़े विमानों की मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ सुविधा) की सुविधा विकसित की जाएगी। यहां पर पायलटों को ट्रेनिंग भी मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार एविएशन विजन एंड पॉलिसी तैयार कर रही है।



सोनपुर और अजगैवीनाथ धाम एयरपोर्ट को बड़े मेंटेनेंस हब के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार विशेष नीति बना रही है। बिहार के सिविल विमानन विभाग के सचिव डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें बताया गया कि इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए बिहार सरकार ने विश्व प्रसिद्ध कंसल्टेंसी एजेंसी केपीएमजी इंडिया सर्विसेज एलएलपी, गुरुग्राम को परामर्शी सेवा के लिए हायर किया है। इस नीति को तैयार करने के लिए राज्य सरकार एजेंसी को करीब 90 लाख (लगभग 86.17 लाख और लागू टैक्स) का सेवा शुल्क देगी। गुरुग्राम स्थित यह एजेंसी बिहार के भौगोलिक और व्यावसायिक लाभ को देखते हुए एक व्यापक एविएशन रोडमैप तैयार करेगी, जिससे अगले कुछ दशकों तक बिहार में हवाई यातायात और रोजगार को गति मिलेगी।

जब भाजपा-सपा ने मिलकर चलाई थी मॉक पार्लियामेंट, लालू बने PM; क्या थी मांग?

पटना (संवाददाता)। यह 2010 की बात है। संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व घटना हुई थी। वामपंथ से लेकर दक्षिणपंथ तक की चार प्रमुख पार्टियों ने मतभेद भुलाकर लोकसभा के भीतर एक घंटे से अधिक समय तक मॉक पार्लियामेंट चलाई थी। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री (प्रतीकात्मक) बनाया गया था। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे ने स्पीकर की भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सांसदों के वेतन वृद्धि के मुद्दे पर भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

सदन की कार्यवाही स्थगित होते ही लालू प्रसाद यादव की पहल पर विपक्षी सांसदों ने कार्यवाही खुद ही आगे बढ़ाने का फैसला किया था। लालू यादव ने सदन में खुद को प्रधानमंत्री के रोल में स्थापित किया। समाजवादी पार्टी (सक्) प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव को उपाध्यक्ष की की जिम्मेदारी दी गई ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके। इस मॉक पर्लियामेंट में भाजपा, वामपंथी दलों, सपा और राजद के लगभग 70 से अधिक सांसदों ने इस मॉक पार्लियामेंट में हिस्सा लिया था। भाजपा नेता मेनका गांधी ने 'मेडिकल काउंसिल बिल' पर भाषण भी दिया, जिसे सरकार ने मूल सदन में बिना चर्चा के पारित करा दिया था। उस समय संसद की सुरक्षा सेवा ने प्रेस गैलरी को तुरंत खाली कराया गया ताकि मीडिया इस ड्रामे को कवर न कर सके। केंद्रीय कैबिनेट ने सांसदों का मूल वेतन 16,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव संसदीय समिति की उस सिफारिश पर अड़े थे जिसमें वेतन 80,000 रुपये करने का सुझाव दिया गया था। लालू का कहना था कि या तो 80,000 रुपये दें या फिर कुछ भी नहीं। कई कांग्रेस सांसद भी गुप्त रूप से लालू के समर्थन में थे और अपनी ही पार्टी के उन नेताओं का विरोध कर रहे थे जो वेतन वृद्धि के खिलाफ थे। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इस पूरी घटना पर कड़ी असंतोष जताया और कहा था, 'संसद लोकतंत्र का मंदिर है और इसके साथ सर्वोच्च सम्मान व गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए।' सत्ताधारी दल के साथ-साथ भाजपा के भी कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र का मजाक करार दिया था। आपको बता दें आज एकबार फिर इसी तरह की कोशिश की गई। हालांकि, इसबार मॉक पार्लियामेंट का आयोजन संसद में नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुआ। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई और एसआईआर की प्रक्रिया को रद्दे करने का प्रस्ताव रखा गया।

सम्राट से मिले निर्दलीय MLC राहुल राज, BJP में होगी वापसी? जेडीयू कैंडिडेट को कम्युनिस्ट बताया



पटना (संवाददाता)। बिहार विधान परिषद चुनाव में सारण शिक्षक एमएलसी सीट से निर्दलीय जीतने वाले राहुल राज ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के बाद राहुल राज की भारतीय जनता पार्टी में वापसी की अटकलें तेज हैं। सारण शिक्षक सीट पर सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी आनंद पुष्कर के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर राहुल राज को पिछले दिनों भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। इस चुनाव में वह जेडीयू उम्मीदवार को हराकर निर्दलीय MLC बन गए। चुनाव में एनडीए से बगावत पर राहुल ने कहा कि जेडीयू ने कम्युनिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया था, इसलिए यह नौबत आई।

MLC राहुल राज ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शनिवार को पटना स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। एमएलसी चुनाव में जेडीयू प्रत्याशियों की हार को लेकर एनडीए में कलह की खबरों के बीच यह मुलाकात हुई। दो दिन पहले तिरहुत स्नातक सीट से निर्दलीय जीते बंशीधर ब्रजवासी ने भी सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। बंशीधर ने तिरहुत में जेडीयू के अभिषेक झा को हराया। वहां भी जेडीयू के नेता भाजपा नेताओं की उदासीनता को हार का वजह बता रहे हैं। सम्राट से मुलाकात करने पहुंचे राहुल राज के साथ सारण से भाजपा के लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद रहे। राहुल ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। सीएम आवास से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर शिक्षकों के मुद्दे उनके सामने रखे, सम्राट ने शिक्षकों की मांगों एवं समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का सकारात्मक आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पटना में मीडिया से बातचीत में MLC राहुल राज ने सारण शिक्षक सीट पर जेडीयू उम्मीदवार आनंद पुष्कर को हराने पर कहा, 'मैंने एनडीए को नहीं हराया, बल्कि कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रत्याशी को हराया। कोई व्यक्ति 10 दिन के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा से आकर एनडीए का उम्मीदवार बन जाता है, तो कार्यकर्ता उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे।' उन्होंने कहा, 'मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। अगर एमएलसी चुनाव में भाजपा या जेडीयू परिवार से कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में होता, तो जैसे 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में त्याग किया, इस बार भी कर देता। पहले भी पार्टी ने जिसे उम्मीदवार बनाया, उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा। पुन: वही काम करूंगा।'राहुल राज ने सारण शिक्षक से जेडीयू के टिकट पर लड़े आनंद पुष्कर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होने पिछला चुनाव लेफ्ट पार्टी सीपीआई से लड़ा था। चुनाव से महज 10-15 दिन पहले उन्होंने जेडीयू जॉइन कर ली। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे।

भाजपा में वापसी पर कहा- घर में ही था, यहीं रहूंगा

राहुल राज ने भाजपा में वापसी पर कहा कि वह इसी घर में थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस विचारधारा से अलग नहीं हुए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राहुल राज की भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक वापसी हो सकती है। वह भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं।

ललन सिंह पर नरम हुए नीरज के तेवर

आशीर्वाद से इनकार के बाद तारीफ की झड़ी

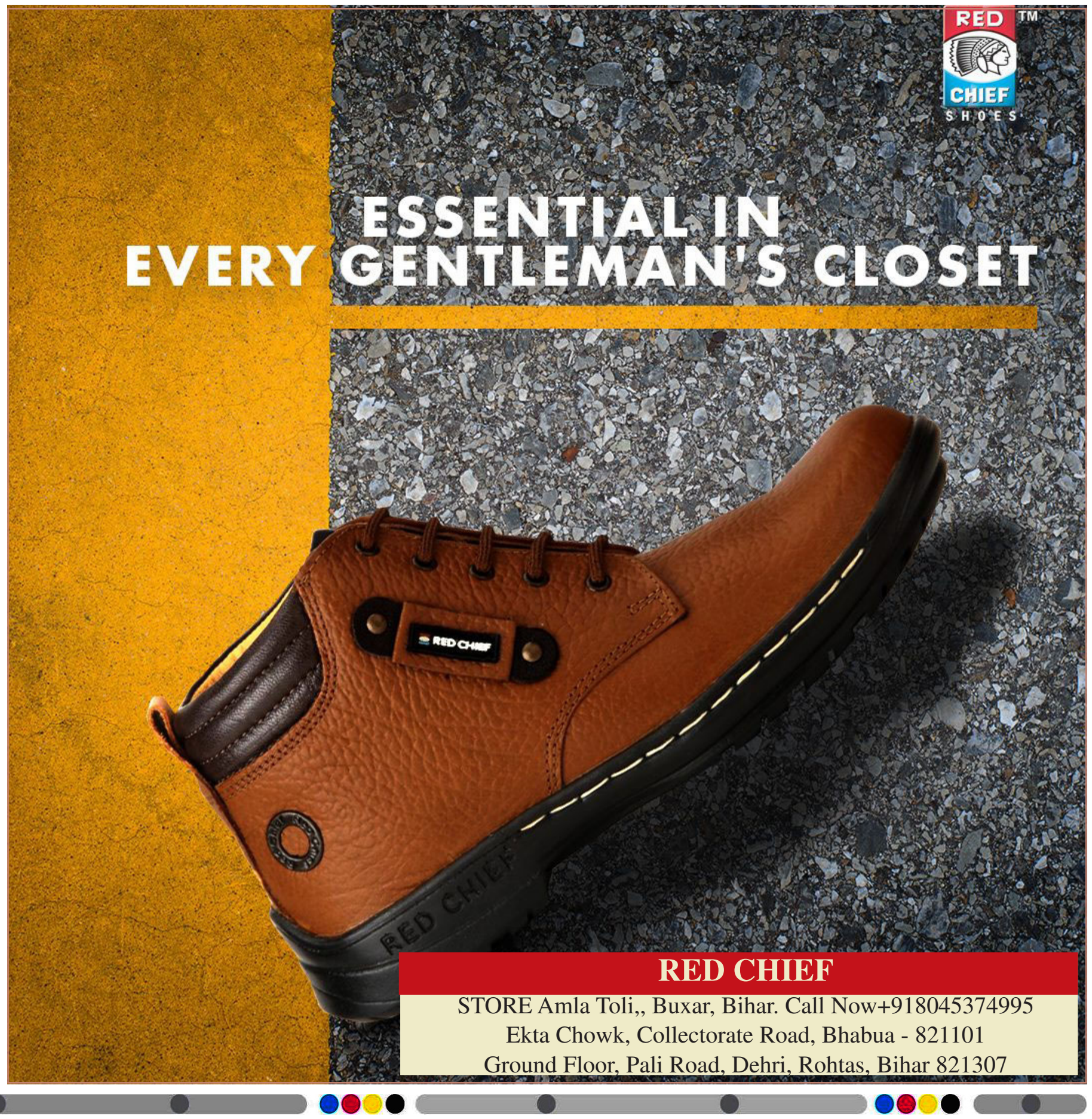


पटना (संवाददाता)। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और पटना स्नातक एमएलसी नीरज कुमार ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड के बड़ा नेता बताया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वे ललन सिंह से जीत की बधाई या आशीर्वाद नहीं लेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बयान के बाद नीरज कुमार के तेवर नरम पड़ गए हैं।

शनिवार को सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर जदयू कार्यालय पहुंचे नीरज कुमार का मूड बदला हुआ दिखा। कभी सूद समेत कर्ज चुकाने का ऐलान करने वाले नीरज कुमार ललन सिंह की तारीफ की झड़ी लगाते नजर आए। ललन सिंह से तल्खी के सवाल पर नीरज ने कहा कि ललन सिंह जनता दल यू के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं इससे कौन इनकार कर सकता है। वे बड़े नेता हैं तब ना केंद्र में मंत्री हैं। जदयू से अभी तक मात्र दो नेता ही केंद्र में मंत्री बन पाए हैं। नीरज कुमार ने कहा कि समता पार्टी की स्थापना से लेकर जदयू के सफर में ललन सिंह की बड़ी भूमिका है।

नीरज ने कहा कि तात्कालिक सवालों को लेकर कुछ मतभेद हुए। यह पार्टी के अंदर का मामला है। पार्टी ने इसे काफी गंभीरता से लिया। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश तक इस मुद्दे पर सजग रहा। चुनाव में हमारी पार्टी की साख बच गई, यह हम सबों के लिए महत्वपूर्ण था।

दरअसल, बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना सीट को लेकर जदयू के तीन नेता तल्खी को लेकर काफी चर्चा में रहे। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने अपने ही दल के अधिकृत उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अनंत सिंह ऐलान कर दिया कि पटना स्नातक सीट पर वे जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह को जीत दिलाएंगे और अपने दल जदयू के घोषित कैंडिडेट नीरज कुमार की जमानत जब्त करा देंगे। उन्होंने नीरज पर चार चुनावों में विरोध करने का आरोप लगाया। इन दोनों के बीच सुलह की जिम्मेदारी ललन सिंह को दी गई पर वह भी कुछ नहीं कर सके। इसके उलट उन्होंने मीडिया में बयान दे दिया कि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया तो होगी ही। ललन सिंह नीरज कुमार के लिए क्षेत्र में भी नहीं दिखे। इस बीच अनंत सिंह और नीरज के बीच बयानों के तीर मीडिया में छाया रहा। पटना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद नीरज कुमार कुमार ने ललन सिंह से दूरी बना ली। यह बात तब सामने आई जब जीत की बधाई दी जा रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीरज कुमार को जीत की बधाई दी।



अन्नदाता किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत की मजबूत आधारशिला : मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी, देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों को 18,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित









छत्तीसगढ़ के 24 लाख 59 हजार 707 किसानों के खातों में पहुंची 498 करोड़ 48 लाख रुपए की सम्मान निधि

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय रायपुर में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल

छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक 11 हजार 776 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की सम्मान निधि प्राप्त

किसानों की आर्थिक मजबूती और खेती को लाभकारी बनाना हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प : मुख्यमंत्री

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में खुलेंगे 360 नए उपार्जन केंद्र

आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर

रायपुर (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके हित में अनेक दूरगामी निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका सशक्त उदाहरण है। इस योजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता उनकी खेती संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के रूप में देश के 9 करोड़ 34 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18 हजार 690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को खेती-किसानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण योजना है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना से आर्थिक संबल मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 59 हजार 707 किसानों के बैंक खातों में 498 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई है। इससे प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक 24 किस्तों में 11 हजार 776 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की गई है, जिससे सहायता वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों को बीज, खाद, उर्वरक और खेती से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के लिए समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गई है। इस योजना से विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों के संचालन में सहायता मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाताओं की छोटी-छोटी आवश्यकताओं को समझकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दूरदर्शी पहल की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के समस्त किसान परिवारों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों की समृद्धि से ही गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कृषि क्षेत्र में बढ़ती आय, बेहतर सुविधाएं और आधुनिक तकनीक का विस्तार विकसित छत्तीसगढ़ तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चक्रवात 'अर्नब' के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान को सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रभावित किसानों को समय पर राहत उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को फसल क्षति का तत्काल सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित किसानों को आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन को प्राथमिकता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित किसान के साथ मजबूती से खड़ी है। किसानों की मेहनत और उनके हितों की रक्षा के लिए राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश में किसानों से 3 हजार 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। यह दर देश में धान खरीदी के लिए दी जाने वाली सर्वाधिक दरों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ की जाएगी। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े तथा उपार्जन केंद्रों में उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 360 नए धान खरीदी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नए उपार्जन केंद्रों के खुलने से किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा होगी। धान खरीदी की प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि किसी भी अन्नदाता को धान बेचने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। किसानों की सुविधा, उनकी मेहनत का उचित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों की आय में स्थायी वृद्धि के लिए खेती को अधिक लाभकारी बनाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग और कृषि आधारित आजीविका के नए अवसर विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती के साथ जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्यपालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन गतिविधियों से किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से शासन की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और आधुनिक एवं लाभकारी कृषि पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के अन्नदाता किसान विकसित भारत के संकल्प की सबसे मजबूत आधारशिला हैं। किसानों की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण के बिना विकसित भारत की परिकल्पना साकार नहीं हो सकती। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। वर्ष 2013-14 की तुलना में आज देश का कृषि बजट पांच गुना बढ़ चुका है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों से 3 हजार 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की व्यवस्था राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक संबल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से किसानों को आर्थिक सहायता, कृषि संसाधन और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। इससे किसानों को खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल रही है। मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि फसल विविधीकरण से किसानों की आय के नए अवसर विकसित होंगे। इससे कृषि क्षेत्र अधिक लाभकारी बनेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में सभापति श्रीमती सविता चंद्राकर, छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन कुमार अग्रवाल, सभापति गुरु सौरभ साहब, कृषि विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव और छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अजय अग्रवाल, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल सहित कृषि विशेषज्ञ, विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल लाई रंग, केंद्रीय सहयोग से विकास योजनाओं को मिली गति

रायपुर (एजेंसी)।

30 अक्टूबर से 3 नवंबर की अवधि में छह केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में मौजूद रहेंगे। इनमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण आवास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया तथा केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी शामिल हैं।

राज्य में डबल इंजन की सरकार होने का सकारात्मक असर छत्तीसगढ़ के तीव्र विकास में नजर आ रहा है। राज्य में विकास योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लगातार दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से संपर्क रखा है। उनके बेहतर समन्वय के चलते केंद्रीय मंत्रियों ने नवाचारी योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को विशेष प्राथमिकता दी है। तीन नवंबर को राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह राजधानी में मौजूद रहेंगे। श्री शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद को देश से जड़ से मुक्त कराने की रणनीति बनी और उन्होंने 31 मार्च 2026 तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा। यह लक्ष्य समय पर पूरा हुआ। श्री शाह ने छत्तीसगढ़ को इस लड़ाई में हर जरूरी संसाधन तथा मनोबल प्रदान किये। नक्सलवाद से लड़ने केंद्रीय सहायता योजना से राशि उपलब्ध कराई। पीएम आवास जैसी योजनाओं से इस समन्वय की झलक मिलती है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य में अब तक 24 लाख 50 हजार



छह केन्द्रीय मंत्री आएंगे छत्तीसगढ़ के दौरे पर

आवास स्वीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, श्री चौहान जब भी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आये, उन्होंने अतिरिक्त पीएम आवासों की घोषणा की। बस्तर के पुनर्निर्माण की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है। इसी दिशा में नक्सल प्रभावित परिवारों एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15 हजार विशेष आवास स्वीकृत किये गये।

अंतरराष्ट्रीय संकटों के चलते खाद की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई। छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, इसके लिए पिछले खरीफ सीजन में मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से पहल की। उन्होंने 50 हजार मीट्रिक टन यूरिया और 50 हजार मीट्रिक टन डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। इस बार भी अतिरिक्त डीएपी केंद्रीय मंत्री ने उपलब्ध कराई। केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता डॉ. वीरेंद्र कुमार 30 और 31 अक्टूबर को रायपुर एवं बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विशेष पहल की है और इसे लेकर उन्होंने डॉ. वीरेंद्र कुमार से अनेक बार चर्चा की है जिसके बाद इन विषयों पर वंचित वर्गों के कल्याण के लिए सार्थक निर्णय लिये गये। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया राज्योत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर के मुख्य अतिथि होंगे। छत्तीसगढ़ में देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुए। यह आयोजन बेहद सफल रहा। केंद्र और राज्य के सहयोग और समन्वय का यह सुंदर उदाहरण बना। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनसे ईएसआईसी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए पहल की थी जिसके बाद यह काम हुआ। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी 3 नवंबर को एनआईटी दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने आ रहे हैं, वे एक समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे। खनन प्रभावित परिवारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री श्री साय का श्री रेड्डी के साथ विमर्श हुआ और इनकी बेहतरी के लिए अनेक निर्णय लिये गये।

चक्रवात 'अर्नब' से प्रभावित किसानों को शीघ्र मिलेगी राहत, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने और पात्र किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

रायपुर (एजेंसी)।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने चक्रवात 'अर्नब' के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान को गंभीरता से लेते हुए सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभावित किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें समय पर राहत मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करे। मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन कर आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण से लेकर सहायता राशि के वितरण तक की पूरी प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिल सके।

मुख्यमंत्री ने अहिवारा विधायक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है कि श्री कोर्सेवाड़ा के निधन की सूचना से वे स्तब्ध हैं। सरल व्यक्तित्व, जनसरोकारों के प्रति संवेदनशीलता और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा उनकी विशेष पहचान रही। क्षेत्र की जनता के सुख-दुःख में सदैव साथ खड़े रहने वाले श्री कोर्सेवाड़ा का निधन हम सभी के लिए गहरी पीड़ा का विषय है। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रभु श्रीराम से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकसंतप्त परिजनों और उनके सभी स्नेहीजनों को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के स्टाल की सराहना की

प्रधानमंत्री ने बस्तर के कलाकारों से की आत्मीय बातचीत

रायपुर (एजेंसी)। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आयोजित भारत पर्व में छत्तीसगढ़ की समृद्ध शिल्पकला, संस्कृति और पर्यटन की झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत पर्व का शुभारंभ करने के बाद छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने नारायणपुर और बस्तर के शिल्पकारों से आत्मीय बातचीत की तथा उनकी कला और हुनर की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्टॉल पर बांस शिल्प एवं अन्य लोकशिल्प का निर्माण कर रहे कलाकारों से शिल्प निर्माण के संबंध में चर्चा की। इस दौरान कलाकारों ने बस्तरिया रेला की प्रस्तुति देकर उनका स्वागत किया। पर्यटन मंडल की डॉ सुभदा चतुर्वेदी ने बताया कि 15 दिनों तक चलने वाले भारत पर्व में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की ओर से लगाए गए स्टॉल में प्रदेश की पारंपरिक हस्तशिल्प कला और पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। यहां डोकरा शिल्प, लौह शिल्प एवं कोसा साड़ियों के साथ बांस शिल्प को भी प्रदर्शित किया गया है। स्टॉल में चंपारण, चित्रकोट सहित छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों और पर्यटन रिसॉर्ट की जानकारी भी प्रस्तुत की गई है।

दीपावली से पहले बस्तर को सड़क विकास की बड़ी सौगात, 485 बसाहटों को मिलेगी बारहमासी सड़कें

उप मुख्यमंत्री शर्मा के प्रयासों को मिला केंद्र सरकार का सकारात्मक प्रतिसाद, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार

रायपुर (एजेंसी)।

दीपावली से पहले बस्तर संभाग के दूरस्थ, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। बस्तर की 485 बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, वहीं 280 अन्य बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 804.06 करोड़ रुपए की लागत के 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान के साथ विकास की गति को तेज करने तथा दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के राज्य सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है।

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा बस्तर संभाग की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों की आवश्यकताओं तथा सड़क एवं पुल संपर्क के विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र के माध्यम से इन क्षेत्रों के लिए विशेष पहल करने के लिए आग्रह किया था, जिसपर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र द्वारा सकारात्मक रुख प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अपने पत्र में बस्तर में सड़क संपर्क विस्तार की प्रगति, स्वीकृत कार्यों, प्रस्तावित सड़कों एवं पुलों तथा विशेष छूट के संबंध में की जा रही कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर के विकास के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति



आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि वर्तमान में बस्तर संभाग की 1,168 बसाहटों से संबंधित सड़क कार्य विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। इनमें से 485 बसाहटों के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के बैच-2 के अंतर्गत 280 बसाहटों को जोड़ने के लिए 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 841.825 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत 804.06 करोड़ रुपए है। वहीं लगभग 474 अन्य चिन्हांकित बसाहटों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के प्रथम बैच में बस्तर संभाग की 234 बसाहटों के सड़क कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें बस्तर जिले की 87, बीजापुर की 44, दंतेवाड़ा की 12, कांकेर की 41, कोण्डागांव की 34 तथा सुकमा की 16 बसाहटें शामिल हैं। पीएमजीएसवाई-4 के दूसरे बैच में बस्तर जिले की 114, बीजापुर की 125, दंतेवाड़ा की 63, कांकेर की 140, कोण्डागांव की 31, नारायणपुर की 136 और सुकमा की 146 बसाहटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके लिए ग्रामीण सड़क सर्वे ऐप द्वारा सर्वे के साथ गति शक्ति योजना के साथ जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इन प्रस्तावित सड़कों के निर्माण से विशेष रूप से अंदरूनी वनांचल क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा। ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, बाजारों और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। साथ ही कृषि उपज के परिवहन, स्थानीय व्यापार और ग्रामीण आजीविका के नए अवसर विकसित होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर में करेंगे बेल्जियम का दौरा, भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते पर होंगे हस्ताक्षर

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का दौरा करेंगे। इस दौरान भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इसकी जानकारी दी है। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इसके लागू होने का रास्ता साफ होगा और भारत तथा यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी।

कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित मॉन्ट्रियल काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक कार्यक्रम में कोस्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर में समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रुसेल्स आएंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा 17 दिसंबर को ब्रुसेल्स में होने वाली यूरोपीय नेताओं की बैठक से ठीक पहले संभावित है। भारत और यूरोपीय संघ ने इस वर्ष की शुरुआत में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत पूरी कर ली थी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाला यह समझौता वैश्विक व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके माध्यम से दो अरब से अधिक लोगों का विशाल बाजार एक साथ आएगा, जो दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। समझौते का प्रमुख उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करना, आयात-निर्यात को आसान बनाना और कारोबारियों के लिए एक-दूसरे के बाजारों तक पहुंच बेहतर करना है।

इस समझौते के तहत भारत को अपने 99 प्रतिशत से अधिक निर्यात के लिए यूरोपीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलने का प्रावधान है। इससे भारतीय कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, रत्न और अन्य निर्यात आधारित उद्योगों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ने के साथ ही निर्यात के नए अवसर भी खुलेंगे। समझौते के बदले यूरोपीय संघ को भारत में निर्यात किए जाने वाले सामान के बड़े हिस्से पर आयात शुल्क में कटौती अथवा छूट मिलेगी। हालांकि, वाहन और वाहन कलपुर्जों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में शुल्क में कमी धीरे-धीरे लागू की जाएगी, ताकि घरेलू उद्योगों को बदलाव के लिए पर्याप्त समय मिल सके। भारत ने अपनी घरेलू कृषि और डेयरी क्षेत्र को इस समझौते के दायरे से बाहर रखा है। इससे इन क्षेत्रों के हितों और घरेलू उत्पादकों के संरक्षण को ध्यान में रखा गया है।



गुजरात के बनासकांठा जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ।

यूपी की कानून-व्यवस्था पर सीएम योगी बोले- हमारी बेटियां सुरक्षित वातावरण में

लखनऊ (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कहा है कि आज बाजार रात में भी खुले रहते हैं। व्यापारियों को व्यवसाय के विस्तार के नए अवसर मिल रहे हैं और हमारी बेटियां सुरक्षित वातावरण में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने इस परिस्थिति को बदला। यूपी की कानून-व्यवस्था पर सीएम योगी बोले- हमारी बेटियां सुरक्षित वातावरण में, डबल इंजन सरकार ने बदली परिस्थिति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, आज नए उत्तर प्रदेश में रात्रि के समय जगमगाते बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की रोशनी केवल व्यापार की नहीं, बल्कि व्यापारी के विश्वास का प्रकाश है। नाइट शिफ्ट में अपने कार्यस्थल पर निर्भय होकर दायित्व निभाती हमारी मातृशक्ति का आत्मविश्वास केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे समाज की प्रगति का प्रतीक है।

उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, किंतु सुरक्षा और विश्वास का यह वातावरण उत्तर प्रदेश में सदैव नहीं था। वर्ष 2017 से पहले अपराध और असुरक्षा के कारण सूर्यास्त के साथ व्यापारिक गतिविधियां सीमित होने लगती थीं। देर रात तक कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर परिवारों में चिंता बनी रहती थी।

सीएम योगी ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने इस परिस्थिति को बदला। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया एवं महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी। आज बाजार रात में भी खुले रहते हैं।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम हटाने के फॉर्म-7 में गड़बड़ी के आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के निर्देश

एक ही समुदाय के लोगों के नाम हटाने के लिए 32 फॉर्म जमा करने का दावा; चुनाव आयोग को शिकायतों की जांच कर अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म-7 को लेकर विवाद गहरा गया है। कुछ स्थानों पर बड़ी संख्या में फॉर्म जमा किए जाने और उनमें कथित अनियमितताओं के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। अदालत ने चुनाव आयोग को शिकायतों में बताए गए तथ्यों की जांच करने और गड़बड़ी पाए जाने पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही आयोग को इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। उनका आरोप था कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन जमा किए गए, जिनकी प्रामाणिकता और प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र में कथित तौर पर 32 फॉर्म-7 जमा किए गए थे। इन सभी प्रपत्रों में एक ही समुदाय के लोगों के नाम शामिल होने का दावा किया गया। याचिकाकर्ताओं ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इस तरह की शिकायतों की सामान्य जांच के बजाय विस्तृत पड़ताल की आवश्यकता है।

उन्होंने कुछ फॉर्म की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, अभिलेखों में मौजूद दो फॉर्म पर बूथ स्तरीय अधिकारियों



(बीएलओ) के हस्ताक्षर दिखाई दे रहे थे। इससे यह सवाल खड़ा हुआ कि आवेदन किसने भरे, किस आधार पर जमा किए गए और उनमें अधिकारियों के हस्ताक्षर किस परिस्थिति में आए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग के जवाब और उपलब्ध दस्तावेजों में कुछ विसंगतियां भी दिखाई देती हैं।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने अदालत को बताया कि आयोग ने इस तरह की शिकायतों की जांच कराई है। संबंधित अधिकारियों ने फॉर्म की पड़ताल करने के साथ उनका दोबारा मिलान भी किया है। आयोग के अनुसार, कुछ शिकायतें जांच में गलत पाई गईं और जिन आवेदनों में गड़बड़ी मिली, उन पर कार्रवाई नहीं की गई।

आयोग की ओर से यह भी कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति के पास किसी विशेष फॉर्म या आवेदन में अनियमितता का ठोस प्रमाण है, तो वह इसकी शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायत मिलने पर उसकी जांच कर उचित कदम उठाए जा सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने आयोग के जवाब पर असंतोष जताते हुए कहा कि केवल शिकायतों को गलत बता देना पर्याप्त नहीं है। जिन दस्तावेजों में आपसी विरोधाभास दिखाई दे रहा है, उनकी अलग-अलग जांच होनी चाहिए। उन्होंने कर्नाटक और तेलंगाना में इसी तरह की शिकायतों के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए जाने का भी हवाला दिया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उत्तर प्रदेश में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।

सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे जिन अनियमितताओं का उल्लेख कर रहे हैं, उनका पूरा विवरण चुनाव आयोग के अधिवक्ता को लिखित नोट के रूप में उपलब्ध कराएं। इसमें उन मामलों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है।

अदालत ने चुनाव आयोग को इस लिखित नोट में शामिल तथ्यों की जांच करने और यह पता लगाने को कहा है कि फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया में वास्तव में कोई अनियमितता हुई है या नहीं। यदि जांच में गड़बड़ी सामने आती है, तो आयोग को उसे दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। इसके बाद आयोग को सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदाता सूची में किसी योग्य नागरिक का नाम दर्ज होना उसके मतदान के अधिकार से सीधे जुड़ा है। यदि किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से हटा दिया जाता है, तो वह चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित हो सकता है। वहीं, गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी का नाम हटाने का प्रयास भी गंभीर अनियमितता माना जाएगा।

भूटान में ग्लेशियल झील फटने से असम और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट, बाढ़ के आसार

भारत-भूटान सीमा तक 6 से 8 घंटे में पहुंच सकता है बाढ़ का पानी, चार हजार लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थलों में भेजा गया

गुवाहाटी (एजेंसी)। भूटान के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में एक विशाल हिमनदीय झील के अचानक फटने से भारत के पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। संभावित आपदा को देखते हुए असम और पश्चिम बंगाल के निचले इलाकों में उच्च सतर्कता जारी कर दी गई है। झील फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण भूटान में सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई परियोजना को नुकसान पहुंचा है, जबकि पुनाखा-गासा राजमार्ग का एक हिस्सा मलबे से बंद हो गया है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, भूटान के गासा जिले में स्थित शिंटाफू झील गुरुवार को अचानक फट गई। यह झील मो-छू नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। झील में पानी का स्तर बढ़ने और उसके प्राकृतिक अवरोध के टूटने से बड़ी मात्रा में पानी तेजी से नदी में पहुंचा है। इसके कारण नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। पानी का बहाव दक्षिण दिशा में होने के कारण इसका असर भारत के असम और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ते तापमान और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हिमनदीय झीलों में प्राकृतिक रूप से निर्मित मलबे के बांध कमजोर हो सकते हैं। इन बांधों में अस्थिरता आने या दरार पड़ने से झील में जमा पानी अचानक बाहर



निकल जाता है। इसी तरह की घटना को हिमनदीय झील विस्फोट से उत्पन्न बाढ़ कहा जाता है। इससे पानी और भारी मात्रा में मलबा तेजी से पहाड़ी घाटियों से होकर निचले इलाकों की ओर बढ़ता है।

शिंटाफू झील से निकला पानी नदी तंत्र के माध्यम से आगे बढ़ सकता है, जिसका संबंध असम की ब्रह्मपुत्र घाटी और पश्चिम बंगाल के उत्तरी दुआर्स क्षेत्र से है। इसी आशंका को देखते हुए दोनों राज्यों के प्रशासन ने आपात निगरानी व्यवस्था सक्रिय कर दी है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए असम के कोकराझार, बक्सा, चिरांग और धुबरी जिलों में चेतावनी जारी की गई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में भी प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र और कूचबिहार में भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

कूचबिहार जिले के तूफानगंज और बॉक्सिरहाट क्षेत्रों में आपातकालीन टीमें तैनात की गई हैं। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बाढ़ का पानी छह से आठ घंटे के भीतर भारत-भूटान सीमा तक पहुंच सकता है। प्रभावित जिलों के अधिकारी नदियों के जलस्तर और पानी के बहाव पर लगातार नजर रख रहे हैं। अचानक आई बाढ़ का असर भूटान में भी देखने को मिला है। पुनाखा जिले के गुमा गेओग के पास दोछुखा-जॉमलिंगथांग-रित्सा चिवोग क्षेत्र में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई जल उत्थापन प्रणाली को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के कारण यह प्रणाली फिलहाल काम करना बंद कर चुकी है। इसके अलावा जॉमलिंगथांग इलाके में पुनाखा-गासा राजमार्ग के एक हिस्से पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री मनोज कुमार ओरांव ने अलीपुरद्वार जिले में संकोश नदी के किनारे रहने वाले लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने भी संकोश नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है।

पीएम-किसान की 24वीं किस्त जारी, देश के 9.34 करोड़ किसानों को मिले 18,700 करोड़ रुपये

रांची (एजेंसी)। भाकृअनुप-राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान, नामकुम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 24वीं किस्त जारी करने के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आयोजित किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में 415 किसानों ने भाग लिया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश के लगभग 9.34 करोड़ किसानों के बैंक खातों में करीब 18,700 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की। कार्यक्रम में संयुक्त सचिव फ्रैंकलिन एल. खोबुंग सहित केंद्र और झारखंड सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में देश में दूध उत्पादन लगभग 1.6 गुना बढ़ा है। साथ ही भारत शहद उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है और समुद्री खाद्य निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्होंने किसानों से इस राशि का उपयोग गुणवत्तापूर्ण बीज और कृषि सामग्री खरीदने में करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि बजट में लगभग पांच गुना वृद्धि कर किसानों के कल्याण और कृषि विकास को नई गति दी है।

नौसेना को मिलेंगे 40 हजार करोड़ के आठ अत्याधुनिक युद्धपोत, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत बढ़ाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण रक्षा परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत नौसेना के लिए आठ अगली पीढ़ी के आधुनिक युद्धपोत (कॉर्वेट) तैयार किए जाएंगे। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। हाल के दिनों में उच्चस्तरीय मंजूरी प्राप्त करने वाली यह प्रमुख रक्षा परियोजनाओं में से एक है।

जानकारी के अनुसार, इन आठ युद्धपोतों का निर्माण दो सरकारी पोत निर्माण कंपनियां करेंगी। इनमें कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) शामिल हैं। दोनों कंपनियों के साथ युद्धपोत निर्माण के अनुबंध पर जल्द हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना से भारतीय नौसेना के सतही युद्धपोत बेड़े की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके साथ ही देश में स्वदेशी युद्धपोत निर्माण उद्योग को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन युद्धपोतों में 70 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा।

परियोजना के तहत तैयार होने वाले युद्धपोत लगभग दो हजार टन क्षमता के होंगे। इनकी अधिकतम गति करीब 30 नॉट यानी लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इन्हें अत्याधुनिक तकनीक और नौसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। अगली पीढ़ी के कॉर्वेट छोटे आकार के तेज गति वाले युद्धपोत होते हैं, जो आधुनिक हथियारों और निगरानी प्रणालियों से लैस रहते हैं। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से तटीय सुरक्षा, समुद्री गश्त और निगरानी के लिए किया जाता है। आकार में ये फ्रिगेट और विध्वंसक युद्धपोतों से छोटे होते हैं, लेकिन इनमें कई प्रकार के आधुनिक हथियार और संवेदक प्रणाली लगाने की क्षमता होती है। ये युद्धपोत समुद्र में दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और हवाई हमलों से मुकाबला करने में सक्षम होंगे। इनके माध्यम से नौसेना को समुद्री सीमाओं की निगरानी, त्वरित कार्रवाई और सामरिक अभियानों में मदद मिलेगी। इन आठ युद्धपोतों में भारतीय नौसेना द्वारा विकसित नया गोपनीय डिजाइन इस्तेमाल किया जाएगा। इनके निर्माण में आधुनिक पोत निर्माण तकनीक का उपयोग होगा।

दिवाली के कारोबार पर असर पड़ने की जताई आशंका

दिल्ली में 1 नवंबर की महारैली टालने की व्यापारियों ने की मांग, राहुल और सोनिया गांधी को लिखा पत्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने एक नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित विपक्षी गठबंधन की महारैली को लेकर चिंता जताई है। व्यापारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर रैली की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि दिवाली के प्रमुख खरीदारी के मौसम में इतनी बड़ी रैली आयोजित होने से बाजारों में आवागमन, यातायात और कारोबार प्रभावित हो सकता है। इससे पहले से ही त्योहारों के दौरान व्यापारिक गतिविधियों पर निर्भर कारोबारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर रैली को एक नवंबर के बजाय दिवाली के बाद 10 नवंबर से आगे आयोजित करने का अनुरोध किया है। वहीं, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने सोनिया गांधी को पत्र भेजकर रैली की तारीख बदलने अथवा आयोजन स्थल को रामलीला मैदान से बदलकर बुराड़ी मैदान करने का सुझाव दिया है।

सदर बाजार व्यापार संघ ने अपने पत्र में कहा है कि धनतेरस और दिवाली के बीच दिल्ली के बाजारों में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होता है। यह समय व्यापारियों के लिए साल के सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसरों में से एक है। ऐसे में विरोध प्रदर्शन, यातायात प्रतिबंध और बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही से बाजारों में ग्राहकों का पहुंचना मुश्किल हो सकता है।

व्यापारियों ने आशंका जताई है कि रैली के कारण लगने वाले यातायात प्रतिबंधों और भीड़भाड़ से दुकानों तक माल पहुंचाने तथा ग्राहकों के आने-जाने में परेशानी होगी। इससे त्योहारों के दौरान होने वाला कारोबार प्रभावित हो सकता है। संगठन ने कांग्रेस नेतृत्व से व्यापारियों की आजीविका और बाजारों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रैली की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की है।

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली के करीब 20 लाख व्यापारी और कारखाना संचालक प्रस्तावित महारैली को लेकर चिंतित हैं। रैली में लगभग 10 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। संगठन का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से दिल्ली के प्रमुख बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात तथा व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

सीटीआई ने स्पष्ट किया है कि व्यापारी रैली के आयोजन का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिवाली के महत्वपूर्ण कारोबारी मौसम में अपनी रोजी-रोटी और व्यापार को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं। संगठन ने दो विकल्प सुझाए हैं। पहला, रैली को 10 नवंबर के बाद आयोजित किया जाए। दूसरा, यदि एक नवंबर को ही रैली करना आवश्यक है तो इसका आयोजन रामलीला मैदान के बजाय बुराड़ी मैदान में किया जाए।

रिपोर्ट के अनुसार, व्यापारिक संगठनों ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से भी संपर्क किया है। इसके अलावा किराना कमेटी दिल्ली ने अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को टालने का अनुरोध किया है।

व्यापारियों का कहना है कि दिवाली के आसपास दिल्ली के बाजारों में ग्राहकों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे समय में बड़े आयोजन से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने पर छोटे और मध्यम कारोबारियों को विशेष रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से एक नवंबर को रामलीला मैदान में यह महारैली आयोजित करने का प्रस्ताव है। रैली का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में आवाज उठाना है। अब व्यापारिक संगठनों की ओर से तारीख और आयोजन स्थल में बदलाव की मांग किए जाने के बाद इस आयोजन को लेकर राजनीतिक और कारोबारी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

वैभव सूर्यवंशी की जगह आए ईशान ने बनाए 0, संजू-अय्यर का भी नहीं चला बल्ला, भारत की हार के 5 बड़े कारण



ऑकलैंड (एजेंसी)। ऑकलैंड के इडेन पार्क स्टेडियम में खेले गए चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों बड़ी हार मिली है। कीवी टीम ने मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 259 रन बनाए और भारत के सामने 260 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआत से लड़खड़ाती रही और जैसे-तैसे 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 172 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने इस मैच को 87 रनों से अपने नाम किया।

मुकाबले में भारत ने अपनी प्लेइंग XI में दो बदलाव किए। पिछले मुकाबले में 19 गेंदों में 45 रनों की पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी की जगह ईशान किशन को खिलाया गया। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की जगह मयंक यादव की वापसी हुई। हालांकि, इन दो बदलावों के बावजूद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। भुवनेश्वर कुमार की जगह आए मयंक यादव ने चार ओवर की गेंदबाजी में 48 रन देकर तीन विकेट लिए। वैभव सूर्यवंशी के स्थान पर आए ईशान किशन के बल्ले से रन नहीं निकले। उन्होंने तीन गेंदों का सामना किया लेकिन बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। इस मुकाबले में इनफॉर्म वैभव सूर्यवंशी के स्थान पर आए ईशान किशन ने शून्य रन बनाए। भारत की हार के क्या पांच बड़े कारण रहे इसकी विस्तार से बात आगे कर रहे हैं।

इस मुकाबले में भारत की हार का सबसे बड़ा कारण तलाशा जाए तो यह निश्चित तौर पर पांचवें गेंदबाज का बेअसर होना है। नीतीश कुमार रेड्डी ने इस सीरीज के पिछले तीन मुकाबलों में अच्छी गेंदबाजी की थी और उन्होंने कप्तान पर अपना भरोसा बरकरार रखा था। यही कारण है कि कप्तान अय्यर ने उन्हें पूरे चार ओवर की गेंदबाजी दी, जिसमें उन्होंने 16 की इकोनॉमी रेट से 64 रन खर्च कर दिए। बेशक उन्हें एक विकेट मिला, लेकिन पांचवें गेंदबाज के इस तरह से बेअसर हो जाने से अन्य गेंदबाजों पर भी दवाब पड़ा और विपक्षी टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही।

यादव डुओ का महंगा साबित होना : भुवनेश्वर कुमार की जगह वापसी करने वाले मयंक यादव ने शुरुआती ओवरों में अच्छा प्रभाव जमाया और 3 विकेट लिए। हालांकि, उन्होंने मुकाबले में चार ओवर की गेंदबाजी करते हुए 48 रन खर्च कर दिए। यह ठीक बात है कि उन्होंने तीन विकेट हासिल किए, लेकिन सटीक गेंदबाजी ना कर पाने के कारण उन्हें ज्यादा रन पड़े। जब मुख्य गेंदबाज को इतने रन पड़ रहे हों तो दूसरे गेंदबाजों का मोराल नीचे जाता है। भारत की हार की एक बड़ी वजह मयंक यादव का महंगा साबित होना रहा। प्रिंस यादव ने इस मुकाबले में एक विकेट चटकाया। सीरीज में पहली बार हुआ जब प्रिंस यादव और मयंक यादव की जोड़ी एक साथ प्लेइंग इलेवन में दिखी। प्रिंस यादव ने इस मुकाबले में चार ओवर में 49 रन खर्चे। उन्हें आखिरी के ओवरों में बेहतर एक्जीक्यूशन वाले गेंदबाजों में गिना जाता है, लेकिन आज सटीक लेंथ से गेंदबाजी करने में प्रिंस कहीं ना कहीं चूकते नजर आए। यादव डुओ द्वारा इस तरह से रन खर्च करने से न्यूजीलैंड बड़े स्कोर तक पहुंचा और भारत को हार का सामना करना पड़ा।

अक्षर और नमन से नहीं बना काम : भारत के पास दो विशेषज्ञ स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव बाहर बैठे हुए हैं। टीम ऑलराउंडर्स के साथ खेलना ज्यादा प्रेफर कर रही है। कई मैचों में जब भारत की बल्लेबाजी चल जाती है तो यह कमजोर कड़ी छिप जाती है, लेकिन आज बल्लेबाजी विभाग के फेल हो जाने के बाद यह स्पष्ट रूप से उजागर हुई। अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 43 रन 14 से अधिक की इकोनॉमी से दिए। अक्षर के कोटे का एक ओवर पूरा करने आए नमन धीर को भी 16 रन पड़ गए। इस तरह इन दोनों ने मिलाकर सिर्फ 1 विकेट लिए और 59 रन खर्च कर दिए।

ईशान किशन का 0, संजू-अभिषेक का फेलियर : भारत की हार का चौथा बड़ा ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी का फेल होना रहा। भारतीय टीम ने पिछले कुछ सालों में अपना दबदबा ऐसा बनाया है कि अगर सामने वाली टीम 250 से ऊपर का लक्ष्य भी रख देती है तब भी लगता है यह चेज हो जाएगा। आज भी फैंस को यही उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भारत के पहले तीन विकेट 50 रनों के स्कोर पर गिर गए थे और 56 रनों के योग पर श्रेयस अय्यर भी चौथे विकेट के रूप में आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी के स्थान पर आए ईशान किशन ने 0 रन बनाए। ओपनिंग में लगातार परिवर्तन से अभिषेक शर्मा भी लय में नहीं रहे। पिछले मैच में वन डाउन और आज ओपनिंग से संजू की भी रिदम टूटी। इस तरह वैभव को ना खिलाने के फैसले ने भी काफी खेल बिगाड़ा। संजू 4 (2) रन और अभिषेक 27 (15) रन बनाए आउट हुए।

अय्यर का लगातार फेलियर, भारत को कर रहा एक्सपोज: श्रेयस अय्यर की भारतीय टी-20 टीम में वापसी बतौर कप्तान हुई है। उन्होंने इस दौरान एक शतक और कुछ अर्धशतक भी लगाए हैं। हालांकि, वे सूर्या के आखिरी फेज की तरह ही प्रदर्शन करने में अनियमित नजर आ रहे हैं। जब भारतीय टीम का ऊपरी क्रम नहीं चलता तब अय्यर के आने और आउट होकर लौट जाने से टीम की यह कमी सामने आ जाती है कि मिडल आर्डर में कुछ ना कुछ कमजोर कड़ी बनी हुई है। आज के मुकाबले में भारतीय टॉप आर्डर के फेल हो जाने के बाद श्रेयस अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वे सिर्फ 11 गेंदों का सामना करते हुए चार चौकों की मदद से 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस सीरीज में अय्यर के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है। वैसे तो उनका नंबर बल्लेबाजी में कई बार आता ही नहीं, लेकिन जब आता है और बहुत जरूरत रहती है तो टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। श्रेयस के आउट होने के बाद नमन धीर और तिलक वर्मा से उम्मीदें थीं, लेकिन आज वे भी नहीं चल सके। अक्षर पटेल का भी बल्ला खामोश रहा। नीतीश कुमार रेड्डी भी बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए। इस तरह भारत ने इस मुकाबले में खराब प्रदर्शन किया और तीन मैचों के बाद सीरीज की पहला हार का स्वाद चखा। सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 1 नवंबर को खेला जाएगा। भारत सीरीज में 3-1 से आगे है।

न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में खेले गए चौथे टी20 मैच में भारत को 87 रनों से मात दी। मैच गंवाने के बाद भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा है कि न्यूजीलैंड की टीम ने बैटिंग पावरप्ले के दौरान खेल को अपने पक्ष में कर लिया था। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की तारीफ की है, जिनके 107 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बनाया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में सात विकेट खोकर 259 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम शुरुआती झटकों से उबर नहीं सकी और 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 172 रन ही बना सकी।

श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों को हार का जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि उन्होंने न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारी की तारीफ भी की। कप्तान को उम्मीद है कि अगले मैच में खिलाड़ी वापसी करेंगे। श्रेयस का मानना है कि बैटिंग पारवप्ले के दौरान मैच हाथ से फिसला। मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, ''हम गेंदबाजी में पीछे रह गए, उन्होंने बैटिंग पावरप्ले में ही लय (मोमेंटम) हासिल कर ली थी। हमने कुछ गेंदबाजों को अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन ग्लेन फिलिप्स को श्रेय जाता है, उन्होंने शानदार पारी खेली। पीछे मुड़कर देखना और सोचना जरूरी है कि हम कहां से वापसी कर सकते हैं। हैमिल्टन जा रहे हैं और बीच में सिर्फ एक दिन है, ऐसे में हमें फिर से रणनीति बनानी होगी और उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा जिन्हें हम बेहतर कर सकते हैं। हमें मैदान के आकार (डायमेंशंस) के बारे में पता था, कुछ खिलाड़ी यहां पहली बार खेल रहे हैं और एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वे अगले मैच में अच्छी वापसी करेंगे।''

भारत के बल्लेबाज रहे फ्लॉफ : लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत की दरकार थी, लेकिन तेज गेंदबाज डफी ने पहले ही ओवर में संजू सैमसन (चार) और ईशान किशन (शून्य) को आउट कर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत ने पहले ओवर के बाद दो विकेट पर महज चार रन बनाए थे। इस शुरुआती झटके से टीम अंत तक नहीं उबर सकी। भारत की ओर से तीसरे विकेट के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर (22) और अभिषेक शर्मा (27) के बीच 46 रन की साझेदारी सबसे बड़ी रही। आमतौर पर आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक इस बार लय में नहीं दिखे। वह मैथ्यू फिशर की गेंद पर कवर में मिचेल सैंटनर को कैच थमा बैठे।

अय्यर ने एडम मिल्ने की गेंद पर जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे स्टंप पर जा लगी। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर दो विकेट लिए। उन्होंने पावरप्ले के बाद भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। भारत ने पावरप्ले में चार विकेट पर 61 रन बनाए।

नमन धीर ने दो छक्कों और दो चौकों की मदद से 13 गेंदों में 28 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही भारत की हार लगभग तय हो गई। तिलक वर्मा ने 35 गेंदों में 35 रन बनाकर टीम को ऑलआउट होने से बचाया। प्रिंस यादव 17 गेंदों में 18 रन बनाकर नाबाद रहे।

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड को मयंक यादव ने शुरुआती झटके दिये। उन्होंने पहले ओवर में टिम साइफर्ट (तीन) को और तीसरे ओवर में डेरिल मिचेल (24) का शिकार किया। मिशेल ने नौ गेंदों की अपनी पारी में दो चौके और दो छक्के लगाये। अक्षर पटेल ने टिक कर खेलने का प्रयास कर रहे फिन एलन (31) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। 11वें ओवर में मयंक यादव ने बेवन जैकब्स (सात) को आउट कर भारत को चौथी सफलता दिलाई।

इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल के बीच 115 रनों की तूफानी साझेदारी ने न्यूजीलैंड के स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। 18वें ओवर में प्रिंस यादव ने ब्रेसवेल को आउट इस साझेदारी का अंत किया। ब्रेसवेल ने 25 गेंदों में चार चौके और छह छक्के उड़ाते हुए 65 रनों की पारी खेली। ग्लेन फिलिप्स ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने अपने शतक के लिए 46 गेंदों का सामना किया। 20वें ओवर जिम्मेदारी नीतीश कुमार रेड्डी को सौंपी गई। उन्होंने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को अभिषेक के हाथों कैच आउट कराकर भारत को सातवीं सफलता दिलाई। ग्लेन फिलिप्स ने 49 गेंदों में छह चौके और 10 छक्के उड़ाते हुए 107 रनों की पारी खेली।

रोहित शर्मा बनेंगे मुंबई इंडियंस के कप्तान, खुद सुझाया था तिलक का नाम; मगर एमआई ने...



नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2027 को लेकर मुंबई इंडियंस के खेमे से बड़ी खबर सामने आई है। अब इस बात पर लगभग मुहर लग गई है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान होंगे। आईपीएल 2024 से पहले इस दिग्गज प्लेयर से मुंबई इंडियंस की कप्तानी ले ली गई थी और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था, लेकिन 3 सीजन लगातार खराब प्रदर्शन के बाद अब फ्रेंचाइजी का हार्दिक से मोहभंग हो गया है और उन्होंने रोहित शर्मा पर एक बार फिर भरोसा जताया है। रोहित शर्मा तीन साल बाद फ्रेंचाइजी की कमान संभालेंगे। हालांकि, फ्रेंचाइजी ने जब उनसे राय मांगी कि किसे कप्तान बनाया जाए तब हिटमैन ने तिलक वर्मा का नाम सुझाया था।

खबर के अनुसार, 'शुरुआत में रोहित ने तिलक वर्मा का नाम सुझाया था, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उनसे कप्तानी संभालने का अनुरोध किया, जिसके लिए वे अब मान गए हैं। न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले कई दौर की बातचीत हुई थी और नए कोचों की नियुक्ति के समय भी रोहित से सुझाव मांगे गए थे।'

रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए 10 साल कप्तानी की। उन्होंने साल 2013 में टीम की कमान तब संभाली जब फ्रेंचाइजी के पास एक भी ट्रॉफी नहीं थी। वह टीम चैंपियन नहीं बनी थी। रोहित शर्मा ने कप्तान बनते ही कमाल किया और पहले ही साल टीम चैंपियन बन गई। उन्होंने 10 साल कप्तानी की जिसमें 5 बार टीम को चैंपियन बनाया। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। रोहित 2013 से 2023 तक मुंबई इंडियंस के कप्तान रहे।

हालांकि, 2020 के बाद मानों फ्रेंचाइजी की किस्मत ही रूठ गई। रोहित शर्मा तीन साल बिना ट्रॉफी जीते कप्तान रहे और जब फ्रेंचाइजी को लगा कि अब किसी और को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए तब उन्होंने हार्दिक पांड्या की तरफ रुख किया। पांड्या ने भी तीन साल तक कप्तानी की लेकिन रिजल्ट में कोई सुधार नहीं हुआ। 6 साल से मुंबई इंडियंस के हिस्से में कोई आईपीएल खिताब नहीं आया है। अब जब साल 2026 में किसी युवा खिलाड़ी या विश्व विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव की ओर ना रुख करके फ्रेंचाइजी रोहित शर्मा की तरफ वापस जा रही है तो क्या वे खिताब दिला पाएंगे और कितने साल तक टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे देखना दिलचस्प होगा। रोहित शर्मा मौजूदा समय में 39 साल से अधिक के हैं।

बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मोमिनुल हक को सिर में लगी भयंकर चोट, कन्कशन सब्सटीट्यूट बने जाकेर अली

ढाका (एजेंसी)। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन फील्डिंग करते समय सिर में चोट लगने के कारण, बांग्लादेश के तीन नंबर के बल्लेबाज मोमिनुल हक की जगह 'कन्कशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर जाकेर अली को टीम में शामिल किया गया है। मोमिनुल हक को यह चोट लंच ब्रेक के ठीक बाद वेस्टइंडीज की पहली पारी के 78वें ओवर में उस समय लगी, जब वह बल्ले के काफी करीब एक कैच पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। बल्लेबाज जोशुआ बिशप ने मेहदी हसन मिराज की ऑफ-स्पिन गेंद को जोर से डिफेंड किया, जिससे गेंद शॉर्ट-लेग पर फील्डिंग कर रहे मोमिनुल के बाईं ओर तेजी से गई। मोमिनुल ने गेंद को पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन उनका गेंद पर से नियंत्रण छूट गया और वह हेलमेट पहने हुए ही मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया।

बांग्लादेश टीम के फिजियो बायजेदुल इस्लाम खान ने एक बयान में बताया कि मोमिनुल के 'सिर में चोट' लगी है। उन्होंने कहा, 'चूंकि उनमें कन्कशन (सिर की चोट से जुड़े लक्षण) के संकेत दिखे हैं। इसलिए मैच के बाकी हिस्से के लिए उनकी जगह जाकेर अली को 'कन्कशन सब्स्टिट्यूट' के तौर पर शामिल किया गया है।' बाद में, जब बंगलादेश ने अपनी दूसरी पारी में अपना तीसरा विकेट गंवाया, तो जाकेर अली बल्लेबाजी के लिए पैड पहने हुए तैयार दिखे। जल्द ही उन्हें मैदान पर उतरना पड़ा, क्योंकि कप्तान नजमुल हुसैन शांतो, रोस्टन चेस की गेंद पर आउट हो गए। यह इस पारी में वेस्टइंडीज के कप्तान (चेस) का तीसरा विकेट था। जाकर ने अभी अपना खाता खोला ही था कि बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा और चाय का ब्रेक समय से पहले लेना पड़ा। शांतो ने मोमिनुल की नियमित नंबर 3 पोजीशन पर बल्लेबाजी की थी।

राशिद खान ने 200 विकेट लेकर रचा इतिहास, अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराकर टी20 सीरीज जीती

शारजाह (एजेंसी)। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 19 रनों से हराकर तीन मैचों की टी 20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इस दौरान कप्तान राशिद खान ने इतिहास रच दिया; वे इस फॉर्मेट में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अफगान स्पिनर ने अपने 120वें टी 20 मैच में यह मुकाम हासिल किया। इस लिस्ट में इंग्लैंड के आदिल राशिद 153 मैचों में 171 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं।



अफगानिस्तान की जीत की नींव खराब शुरुआत के बाद शानदार बल्लेबाजी से पड़ी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगान टीम पावरप्ले के अंदर ही 5/4 के स्कोर पर लड़खड़ा गई थी और नौवें ओवर में उनका पांचवां विकेट भी गिर गया। हालांकि अजमतुल्लाह उमरजई और एजाज अहमदजई ने शानदार वापसी करते हुए 142 रनों की साझेदारी की। टी 20 क्रिकेट में छठे या उससे निचले क्रम के विकेट के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है।

उमरजई ने अपने करियर का पहला टी 20 शतक जड़ा और 116 रनों की तूफानी पारी खेली। वे इस फॉर्मेट में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उनकी पारी में 12 छक्के और 5 चौके शामिल थे, जबकि अहमदजई ने 52 रनों का अहम योगदान दिया। इन दोनों की बदौलत अफगानिस्तान ने 20 ओवरों में 221/7 का स्कोर खड़ा किया। टी 20 क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी टीम ने अपने शुरुआती 4 विकेट 20 रन से कम के स्कोर पर गंवाने के बाद 200 से ज्यादा रन बनाए हों। यह इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है। जवाब में जिम्बाब्वे के सामने एक मुश्किल लक्ष्य था और वे शुरुआत से ही दबाव में आ गए। पारी के बीच में 85 रन पर 5 विकेट गंवाने के बावजूद मेजबान टीम ने आखिरी 10 ओवरों में संघर्ष जारी रखा। कप्तान सिकंदर रजा ने अपने दूसरे टी 20 शतक के साथ जिम्बाब्वे की ओर से मोर्चा संभाला; उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 9 छक्के लगाए। हालांकि उनकी कोशिश अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थी और अफगानिस्तान ने डटे रहकर एक यादगार जीत हासिल कर ली। इस जीत से अफगानिस्तान को तीन मैचों की सीरीज में एक ऐसी बढ़त मिल गई जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता। साथ ही यह मौका राशिद खान के लिए भी ऐतिहासिक बन गया, जो पुरुषों के टी 20 क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए।

अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए रचा इतिहास, 99 पारियों में 150 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 मैच में ये उपलब्धि हासिल की। ऑकलैंड में अर्शदीप ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर को आउट करके ये कारनामा किया। इसी के साथ वह सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले (गेंद के लिहाज से) दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स के दमदार शतक की मदद से 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 259 रन बनाए।



टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 150 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा के नाम है। उन्होंने 2035 गेंदों में 150 विकेट हासिल किए। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने 2098 गेंदों में ये कारनामा किया था, जबकि भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 2143 गेंदों में 150 विकेट चटकाए हैं। एहसान खान ने 2320 गेंदों में ये कमाल किया है।

अर्शदीप ने चौथे मुकाबले से पहले टी20 इंटरनेशनल में 102 मैचों में 149 विकेट चटकाए थे। उन्होंने शुक्रवार को मिचेल सैंटनर को आउट करके टी20 इंटरनेशनल में अपने 150 विकेट पूरे किए। अर्शदीप 99 पारियों में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। उनसे पहले 100 से कम पारियों में 150 विकेट लेने का कारनामा सिर्फ दो स्पिनरों ने किया है। श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने 90 पारियों में ऐसा किया था, जबकि राशिद खान ने 92 पारियों में 150 विकेट झटके। टी20 इंटरनेशनल में अब तक कुल 9 गेंदबाज 150 या उससे अधिक विकेट लेने में सफल रहे हैं। सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड राशिद खान के नाम है। उन्होंने 119 टी20 इंटरनेशनल मैच में 199 विकेट चटकाए हैं। ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल की विस्फोटक पारियों के दम पर न्यूजीलैंड ने चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत के खिलाफ सात विकेट पर 259 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ किसी भी टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाए और भारतीय गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी। तीसरे टी-20 में भारतीय बल्लेबाजों ने भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पांच मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली थी। फिलिप्स ने 49 गेंदों पर 107 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि ब्रेसवेल ने महज 25 गेंदों पर 65 रन बनाये दिए। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए केवल 41 गेंदों में 115 रन की साझेदारी कर भारतीय गेंदबाजी की कलई खोल दी।

संपादकीय

सरकार की मंजूरी ही निर्णायक

जजों की नियुक्ति में सरकार की मंजूरी ही निर्णायक रही, तो फिर कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच अलगाव के सिद्धांत का क्या हुआ? और क्या इसे तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्पण नहीं माना जाएगा?

भारतीय संविधान में अपनाए गए शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के तहत न्यायपालिका की स्वायत्त हैसियत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की कि ये विभाजन संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। इसी आधार पर उसने 1993 और 1998 में दिए दो निर्णयों के जरिए उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम कायम किया। इस प्रणाली की अक्सर यह कहकर आलोचना की गई है कि इससे सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में सरकार और विधायिका की भूमिका खत्म कर दी और उसने खुद को 'स्वायत्त' की जगह 'स्वतंत्र' बना लिया।

ऐसा सिस्टम शायद ही किसी और लोकतांत्रिक देश में हो! मगर भारत की विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्णतः न्यायपालिका के दायरे में रखने के चलन को व्यापक जन-समर्थन रहा है। यह इस भरोसे रहा है कि इससे शासन व्यवस्था में अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत को व्यावहारिक बनाए रखने में मदद मिलेगी। अब सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के व्यवहार के बारे में जो कहा है, उसे इसी बड़े संदर्भ में देखना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कॉलेजियम के जरिए जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजने के पहले जजों की लिस्ट पर सरकार की मंजूरी लेते थे। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि चंद्रचूड़ सरकार के प्रति 'अत्यधिक सम्मान की भावना' रखते थे।

इन टिप्पणियों से सर्व-प्रमुख प्रश्न यही उठता है कि अगर अंततः सरकार की मंजूरी ही निर्णायक पहलू रहा, तो फिर कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच अलगाव के सिद्धांत का क्या हुआ? और क्या इसे तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्पण नहीं माना जाएगा? फिलहाल, दावा सिर्फ एक प्रधान न्यायाधीश के व्यवहार के बारे में किया गया है, लेकिन हालिया वर्षों में उच्चतर न्यायपालिका के संबंध में इससे मिले-जुले सवाल अक्सर उठते रहे हैं। ये प्रश्न खुद न्यायपालिका में खास भूमिका रखने वाली शख्सियतों ने उठाए हैं। इन चर्चाओं ने कोर्ट की भूमिका को लेकर परिदृश्य को मटमैला कर दिया है। वर्तमान माननीय न्यायाधीशों को इस पर तुरंत गौर करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका के साथ-साथ पूरी संवैधानिक व्यवस्था की साख दांव पर है।

अरबों से बगावत, यहूदियों से 'रक्त-संधि'

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम। अर्थात हे भारत, जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब-तब मैं धर्म की स्थापना के लिए स्वयं को प्रकट करता हूँ। विश्व इतिहास में महाभारत के युद्ध को धर्मयुद्ध कहा गया। लेकिन महाभारत के लिए जो युद्ध लड़ा गया था वो किसी धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं बल्कि सत्य और न्याय की समाज में स्थापना के लिए लड़ा गया था। इसका उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करके दूसरे धर्मों का क्रूर दमन करना नहीं था और न ही उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करना था। दुनिया के सभी धर्मों को दो हिस्सों में अब्राहिम रिलीजन और इंडियन रिलीजन में बांटा गया है। अब्राहिम रिलीजन में ईसाई, यहूदी और मुसलमान आते हैं तो वहीं इंडियन रिलीजन में बुद्धिस्ट, हिंदू और सिख जैसे बहुत सारे धर्म शामिल हैं, जिनकी जड़े हमारे भारत देश से मिलती हैं। यानी इनकी स्थापना और शुरुआत भारत देश से ही कि गई थी। ईसाई धर्म जब अपनी ठीक ठाक जगह यूरोप में बना चुका था। उस वक्त ईसाई जब अपने धर्म का विस्तार कर रहे थे, तो उनका नारा सिर्फ और सिर्फ समाज में मोहब्बत बांटने का था। जीसस क्राइस्ट शोअर्ड अस, हाऊ टू लव अदर्स यानी जीसस ने हमें बताया है कि लोगों से कैसे मोहब्बत की जाए। लेकिन सवाल ये था कि जिनकी जुबान पर जीसस के नाम पर मोहब्बत बांटने वाले गीत थे, उन्होंने क्रूसेड का रास्ता क्यों चुना? लोगों को नफरत छोड़कर प्यार बांटने के गीत गाने वालों ने पूरे यूरोप में तबाही क्यों मचाई और वो भी दूसरे धर्म वालों का नरसंहार करके। इसी को द क्रूसिड के नाम से जाना जाता है।

बाइबल में कहा गया है कि यह भूमि यहूदियों के लिए है, और पवित्र धर्मग्रंथों से असहमति नहीं जताई जानी चाहिए। मैं और मेरे लोग यहूदी राज्य के वफादार नागरिकों के रूप में शांति से रहना चाहते हैं, '— यह बात गैलिली (उत्तरी इज़राइल) के मुस्लिम बदू अल-हैब जनजाति के प्रमुख शेख हुसैन इस्माइल अबू यूसुफ ने 1948 की शुरुआत में यिगल एलोन से कही थी। एलोन ब्रिटिश-शासित फ़िलिस्तीन में यहूदियों के विशिष्ट सैन्य बल 'पलमाच' के कमांडर थे। मई 1948 में इज़राइल द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा करने से कुछ महीने पहले, अबू यूसुफ ने यहूदी बलों के साथ गठबंधन की मांग की थी। इसके बाद उनकी जनजाति के लगभग 70 युवकों को यहूदी सेना के साथ मिलकर लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया। एक ऐसे समय में जब यहूदी सेनाएँ फ़िलिस्तीनी अरब समूहों से लड़ रही थीं और इज़राइल का अस्तित्व में आना बाकी था, एक मुस्लिम अरब प्रमुख की ओर से यह एक असाधारण घोषणा थी। जब अबू यूसुफ ने यह निर्णय लिया, तब फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन अपने अंत के करीब था, और यहूदी व फ़िलिस्तीनी अरब सेनाएँ उस क्षेत्र के भविष्य को लेकर आपस में लड़ रही थीं। जहाँ अधिकांश अरब दुनिया एक यहूदी राष्ट्र के निर्माण का विरोध कर रही थी, वहीं इस क्षेत्र में कुछ ऐसे मुस्लिम बदू कबीले भी थे जिन्होंने यहूदियों का समर्थन करने का फैसला किया। यूसुफ के नेतृत्व वाली अल-हैब जनजाति भी उन्हीं में से एक थी। इस कबीले के सदस्यों ने खुफिया जानकारी दी, यहूदी लड़ाकों की मदद की और एक ऐसी सैन्य



इकाई में शामिल हुए जिसने उस युद्ध में हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप इज़राइल की स्थापना हुई। हालाँकि यह कहानी मध्य पूर्व में यहूदी-अरब प्रतिद्वंद्विता के बारे में आज की धारणा को चुनौती देती है, लेकिन यह यह भी दिखाती है कि किस तरह संघर्ष और विजय ने यहूदियों और अरबों को, और यहाँ तक कि अरब समुदायों को भी आपस में बाँट दिया। इज़राइल के गठन के लगभग आठ दशक बाद, यहूदियों और अरबों के बीच के संबंध वहां की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। 27 अक्टूबर के चुनाव के नतीजों के अनुमान के मुताबिक, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गुट को 53 सीटें और उनके प्रतिद्वंद्वी गादी आइसेनकोट के गुट को 48 सीटें मिल सकती हैं। 120 सदस्यों वाली 'नेसेट' (इज़राइली संसद) में बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है, जो दोनों गुटों के पास नहीं हैं। अरब पार्टियों ने रिकॉर्ड 19 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है और वे 'किंगमेकर' की भूमिका में आ सकती हैं। यह स्थिति तब है जब यहूदी नेतृत्व वाले कई विपक्षी दल, इज़राइल की दो अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर रहने से कतराते रहे हैं। इस गतिरोध और इज़राइली अरब मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए विदेशी फंडिंग मिलने के आरोपों ने, इज़राइल में यहूदी-अरब संबंधों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में, मुस्लिम बेदुइन लोगों की कहानी आज और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसे याद करना प्रासंगिक है।

20वीं सदी की शुरुआत में फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 'होलोकॉस्ट' (यहूदियों के नरसंहार) के बाद यह मांग और भी प्रबल हो गई। इस नरसंहार में एडोल्फ हिटलर के नाज़ी जर्मनी और उसके सहयोगियों ने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी। इस नरसंहार और बचे हुए यहूदियों की दयनीय स्थिति ने एक यहूदी राष्ट्र की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन को और बढ़ा दिया। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ब्रिटिश शासन वाले फिलिस्तीन को बांटकर एक यहूदी और एक अरब देश बनाने का सुझाव दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि भारत उन 13 देशों में शामिल था, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की इस विभाजन योजना के खिलाफ वोट दिया था। यहूदी नेतृत्व ने विभाजन योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन फ़िलिस्तीनी अरब नेताओं और पड़ोसी अरब देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उस समय फ़िलिस्तीन ब्रिटिश शासन के अधीन था, और आप्रवासन, भूमि और क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों को लेकर यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव बढ़ रहा था। यहूदी समूह एक राष्ट्रीय मातृभूमि स्थापित करना चाहते थे, जबकि फ़िलिस्तीनी अरब यहूदी मांगों का विरोध कर रहे थे और अपनी भूमि पर नियंत्रण खोने से भयभीत थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बाद, हगानाह सहित यहूदी सैन्य संगठनों और स्थानीय मिलिशिया और लड़ाकों सहित फ़िलिस्तीनी अरब सशस्त्र समूहों के बीच लड़ाई छिड़ गई। मुख्य यहूदी सैन्य संगठन हगानाह और उसकी विशिष्ट लड़ाकू टुकड़ी, पल्माच ने यहूदी बस्तियों की रक्षा और सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे ही ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन से हटने की तैयारी की, संघर्ष और तीव्र हो गया। इसने इज़राइल की स्वतंत्रता की घोषणा का मार्ग प्रशस्त किया। यहूदियों के मुख्य सैन्य संगठन 'हगाना' और उसके विशिष्ट लड़ाकू बल 'पाल्माच' ने यहूदी बस्तियों की रक्षा करने और सैन्य अभियान चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे-जैसे ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से हटने की तैयारी की, संघर्ष और तेज हो गया। इसी पृष्ठभूमि में मई 1948 में इज़राइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके बाद पड़ोसी अरब देशों के साथ युद्ध छिड़ गया। 14 मई 1948 को डेविड बेन-गुरियन ने इज़राइल की स्वतंत्रता की घोषणा की। अगले दिन, मिस्र, ट्रांसजॉर्डन (अब जॉर्डन), सीरिया और इराक की सेनाएँ युद्ध में शामिल हो गईं। लेबनान ने भी इसमें हिस्सा लिया। यह युद्ध 1949 तक चलता रहा। इज़राइल न केवल बचा रहा, बल्कि उसने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना में यहूदी राज्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से भी कहीं अधिक ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। फिलिस्तीनियों के लिए, यह युद्ध 'नक्बा' यानी एक बड़ी तबाही बन गया, जिसके दौरान लगभग 7 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा या उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन, यह लड़ाई कोई ऐसी सीधी-सादी स्थिति नहीं थी जहाँ सभी अरब एक तरफ होकर सभी यहूदियों के खिलाफ लड़ रहे हों। कुछ अरब समुदायों ने यहूदी सेनाओं का समर्थन किया, कुछ ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और कुछ तटस्थ रहने की कोशिश करते रहे। यहूदियों का पक्ष चुनने वालों में 'अल-हैब' कबीले के मुस्लिम बेदौइन (खानाबदोश) लोग भी शामिल थे। वे गैलिली क्षेत्र में 'तूबा' गाँव के आसपास रहते थे। यह इलाका उस समय ब्रिटिश शासन वाले फिलिस्तीन का हिस्सा था, और आज उत्तरी इज़राइल में 'तूबा-ज़ंगारिये' नामक कस्बे के रूप में जाना जाता है।

भारत की कृषि गाथा का नया रूप: परिवर्तन का एक दशक

जब माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में पदभार संभाला, तब कृषि और किसान कल्याण को भारत के विकास एजेंडे के केंद्र में रखा गया। वर्ष 2015 से यह प्रतिबद्धता उत्पादन और कृषि आय में सुधार से आगे बढ़कर कृषि क्षेत्र को अधिक उत्पादक, सुदृढ़, प्रौद्योगिकी-आधारित और टिकाऊ बनाने के व्यापक परिवर्तन में परिलक्षित हुई है। प्रधानमंत्री ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि विकसित भारत के लिए भारतीय कृषि का भी विकास होना चाहिए।

उन्होंने यह भी आह्वान किया है कि भारत केवल अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित न रहे, बल्कि वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरे। लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान, जय किसान और अटल बिहारी वाजपेयी के जय विज्ञान के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने देश को जय अनुसंधान का मंत्र दिया। इस मंत्र के माध्यम से उन्होंने अनुसंधान और नवाचार को भारत की कृषि के भविष्य के केंद्र में स्थापित किया। ये शब्द केवल नीतिगत दिशा का वक्तव्य नहीं थे, बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टि के परिचायक थे, जिसकी दूरदर्शिता और विवेक की पुष्टि एक दशक बाद सामने आए साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से हुई।

यह विजन भारतीय कृषि को देखने के हमारे दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। हरित क्रांति ने भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान की। आज हमारी जिम्मेदारी पोषण सुरक्षा, किसानों की समृद्धि, संसाधन सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की मजबूत नींव तैयार करना है। भारत की कृषि यात्रा उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरी रही है। कभी खाद्य आयात पर निर्भर रहने वाला भारत कुछ ही दशकों में प्रमुख अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। हरित क्रांति को विज्ञान, उन्नत बीजों, सिंचाई, बुनियादी ढांचे, संस्थागत ऋण, कृषि विस्तार सेवाओं और नीतिगत सहायता से गति मिली। इससे यह सिद्ध हुआ कि जब वैज्ञानिक क्षमता और राजनीतिक प्रतिबद्धता किसी राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए एक साथ आती हैं, तो क्या कुछ अर्जित किया जा



सकता है। लेकिन कृषि को अतीत की प्राथमिकताओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। किसानों की आकांक्षाएं बदल गई हैं, नागरिकों के उपभोग के तौर-तरीके बदल गए हैं, बाजार बदल गए हैं और जलवायु भी बदल रही है।

इसलिए वर्ष 2015 से जारी परिवर्तन महत्वपूर्ण है। वर्ष 1995-96 और 2014-15 को संरचनात्मक बदलाव के महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है, क्योंकि ये भारतीय कृषि के विकास के अलग-अलग चरणों को दर्शाते हैं। पहला चरण आर्थिक उदारीकरण के क्रमिक प्रभाव, बाजारों के साथ बढ़ते एकीकरण, बदलते उपभोग पैटर्न और अनाज उत्पादकता वृद्धि की धीमी गति को दर्शाता है। दूसरा चरण सिंचाई के विस्तार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बाजार सुधारों तथा स्थिरता और जलवायु अनुकूलन पर बढ़ते ध्यान से प्रेरित अधिक विविधीकृत, प्रौद्योगिकी-सक्षम और सुदृढ़ कृषि प्रणाली के उभार का संकेत देता है। कृषि विकास की औसत दर 1967-1995 के दौरान लगभग 2.7 प्रतिशत और 1996-2014 के दौरान लगभग 3.0 प्रतिशत थी। यह 2015-2025 के दौरान बढ़कर लगभग 4.5 प्रतिशत हो गई (खाद्यान्न उत्पादन में 8.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष, फल एवं सब्जियों में 7.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा दूध में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। पिछले दो वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई, जो प्रति वर्ष 22.1 मिलियन टन रही और पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अधिक है। यह उपलब्धि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, कार्यक्रमों के प्रभावी संयोजन, जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण, लक्षित निवेश और किसानों को बढ़े हुए समर्थन के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वृद्धि अब व्यापक आधार पर हो रही है और इसे केवल अनाज ही नहीं, बल्कि बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन तथा अन्य उच्च-मूल्य वाले कार्यकलापों से भी बल मिल रहा है। यही कृषि भारत के विकास के अगले चरण को गति देगी।

हमारा उद्देश्य अब केवल अधिक उत्पादन तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें कम संसाधनों—कम पानी, कम भूमि, कम ऊर्जा और अनावश्यक कृषि आदानों के कम उपयोग—के साथ अधिक उत्पादन करना होगा, साथ ही बेहतर गुणवत्ता वाला, सुरक्षित और अधिक पौष्टिक खाद्य तैयार करना होगा। भारत में उपभोग के बदलते स्वरूप से भी इसका स्पष्ट संकेत मिलता है। ग्रामीण भारत में 1972-73 में खाद्य व्यय का लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा अनाज पर खर्च होता था; 2022-23 तक यह घटकर लगभग 11 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में दूध और दुग्ध उत्पादों, फलों, सब्जियों, अंडों, मांस और मछली का हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत से बढ़कर करीब 48 प्रतिशत हो गया। शहरी क्षेत्रों में भी उपभोग का रुझान इसी तरह बदला है। हमारी कृषि को इस नए भारत की आवश्यकताओ के अनुरूप ढलना होगा। इसका अर्थ है दलहनों तिलहनों, फलों, सब्जियों, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और अन्य उच्च-मूल्य वाली कृषि उपज पर अधिक ध्यान देना। इसका अर्थ खाद्य सुरक्षा की सीमित अवधारणा से आगे बढ़कर पोषण सुरक्षा की दिशा में बढ़ना भी है। किसानों को उन मूल्य शृंखलाओं से जोड़ना आवश्यक है, जहां वास्तविक आर्थिक अवसर तेजी से ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स और निर्यात में केंद्रित हो रहे हैं।

भारत सरकार ने इस बदलाव के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा दे रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पहल ने मिट्टी की जांच और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को कृषि संबंधी निर्णयों के केंद्र में रखा है। पीएम-कुसुम कृषि को नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ रही है। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सामूहिक उपज-संग्रह और सौदेबाजी की क्षमता को सुदृढ़ कर रहे हैं। ई-नाम कृषि बाजारों को डिजिटल रूप से जोड़ रहा है, जबकि कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और पीएमएफएमई फसल कटाई के बाद की अवसंरचना और प्रसंस्करण को मजबूत कर रहे हैं। अब इन पहलों को बीज से मिट्टी तक, खेत से बाजार तक और प्रयोगशाला से आजीविका तक एकीकृत किसान-केंद्रित मूल्य शृंखला में समाहित करना होगा। इस परिवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिका केंद्रीय होगी।

सिर की खुजली से परेशान हैं? इन प्राकृतिक तरीकों से पाएं राहत

सिर की खुजली एक आम समस्या है, जो कई लोगों को परेशान करती है। यह समस्या सिर में खुजली, जलन और कभी-कभी त्वचा पर लालिमा भी ला सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रूसी, गंदगी का जमा होना या एलर्जी। इस लेख में हम आपको कुछ प्राकृतिक उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपनी सिर की खुजली का इलाज कर सकते हैं और राहत पा सकते हैं।

नारियल तेल एक प्राकृतिक नमी देने वाला है, जो आपके सिर को नमी प्रदान करता है और खुजली को कम करता है। इसे उपयोग करने के लिए थोड़े-से नारियल तेल को हल्का गर्म करें और फिर इसे अपने सिर पर अच्छी तरह लगाएं। 30 मिनट तक मसाज करने के बाद इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, फिर सामान्य शैंपू से धो लें। यह प्रक्रिया हफ्ते में 2 बार करें ताकि आपको जल्द राहत मिले।

एलोवेरा जेल में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो खुजली वाले सिर को आराम पहुंचाते हैं। इसके लिए ताजे एलोवेरा पत्ते से जेल निकालें और इसे अपने सिर पर लगाएं। 15-20 मिनट तक छोड़ने के बाद इसे पानी से धो लें।

यह उपाय आपके सिर की त्वचा को ठंडक देगा और खुजली को कम करेगा। एलोवेरा जेल का नियमित उपयोग आपके सिर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा।

नीम का तेल कीटाणु नाशक और फंगल संक्रमण को रोकने वाले गुणों से भरपूर होता है, जो रूसी और खुजली का कारण बन सकते हैं।

इसे उपयोग करने के लिए नीम के तेल को नारियल तेल के साथ मिलाकर हल्का गर्म करें, फिर इसे अपने सिर पर लगाएं और मसाज करें। 30 मिनट तक छोड़ने के बाद इसे पानी से धो लें। यह उपाय हफ्ते में 1 बार करें ताकि आपको जल्द राहत मिले। दही में ऐसे तत्व होते हैं, जो आपके सिर की त्वचा को पोषण देते हैं और खुजली को कम करते हैं। इसके लिए थोड़ी दही लें और उसमें नींबू का रस मिलाएं, फिर इसे अपने सिर पर लगाएं और 20 मिनट तक सूखने दें। सूखने के बाद इसे पानी से धो लें।

यह उपाय हफ्ते में 2 बार करें ताकि आपको जल्द राहत मिले। दही का नियमित उपयोग आपके सिर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। सेब का सिरका आपके सिर के संतुलन को बनाए रखता है, जिससे खुजली कम होती है। इसके लिए एक कप पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाएं, फिर इसे अपने सिर पर स्प्रे करें और हल्का मसाज करें।

वनांचल में जगी शिक्षा की नई अलख : सुदृढ होती उच्च शिक्षा और विकास की बयार

छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल और आदिवासी बहुल अंचलों में सेवा आपके द्वार और सेवा का संकल्प अब महज प्रशासनिक नारे या सरकारी घोषणाएं नहीं रह गए हैं। यह धरातल पर एक सशक्त, व्यापक और स्थायी सामाजिक बदलाव का जीवंत माध्यम बन चुके हैं। राज्य सरकार का मूल ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि विकास की रोशनी केवल बड़े महानगरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे सुदूर ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों के हर नागरिक तक पहुंचे। इसी दूरदर्शी सोच के तहत आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के प्रसार और मजबूत अधोसंरचना के निर्माण के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसी प्रशासनिक प्रतिबद्धता का एक प्रेरणादायक उदाहरण हाल ही में धमतरी जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र नगरी में देखने को मिला है।

धमतरी जिले का नगरी अंचल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए विख्यात है, लेकिन लंबे समय से यहां शैक्षणिक संसाधनों के विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। क्षेत्र के प्रमुख उच्च शिक्षा केंद्र, शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी में अतिरिक्त अध्ययन कक्षों, आधुनिक प्रयोगशालाओं और बेहतर पठन-पाठन सुविधाओं की कमी थी। वनांचल के प्रतिभावान युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने और उनकी राह को सुगम बनाने के उद्देश्य से, प्रदेश के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने महाविद्यालय परिसर में 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अतिरिक्त कक्ष भवन का लोकार्पण किया। यह नवनिर्मित भवन केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा मात्र नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के सैकड़ों छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा की आकांक्षाओं का मजबूत प्रतीक है। यह आधुनिक भवन विद्यार्थियों को उन्नत अध्ययन, शोध कार्य, अकादमिक सेमिनार, कार्यशालाओं और विभिन्न सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए एक सर्वसुविधायुक्त और शांत शैक्षणिक वातावरण प्रदान करेगा। इसके साथ ही क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने के लिए नगर पंचायत नगरी क्षेत्र में नागरिकों की दैनिक सहूलियत और जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाले कई अन्य बुनियादी विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया गया। यह कदम इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार शिक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए भी पूरी तरह संकल्पित है।

उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने राज्य सरकार के विजन को रेखांकित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक और मजबूत आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारे युवा ही एक स्वर्णिम छत्तीसगढ़ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण की वास्तविक नींव हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद निरंतर प्रयास, अटूट लगन और अनुशासन के बल पर ही प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य गढ़ा जा सकता है। यह नया ढांचागत विकास वनांचल के विद्यार्थियों में एक नया उत्साह, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की ऊर्जा का संचार करेगा।

सुदूर वनांचल में बुनियादी ढांचे का यह ऐतिहासिक विकास इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अब विकास की गति केवल राजधानी या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। सेवा आपके द्वार की भावना के साथ जब शासन स्वयं नागरिकों के द्वार तक पहुंचता है, तो इसके परिणाम बेहद सुखद और दूरगामी होते हैं। शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय में हुए इस विस्तार से अब आसपास के दर्जनों गांवों के आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। अपने ही क्षेत्र में उच्च स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं मिलने से विशेष रूप से बालिकाओं और छात्राओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी में तेजी से वृद्धि होगी। संसाधनों का यह सुलभ विस्तार वनांचल के युवाओं की सोच और उनके जीवन स्तर में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला रहा है। शिक्षा के माध्यम से सशक्त होते ये युवा न केवल अपना और अपने परिवार का भविष्य संवार रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की समग्र प्रगति और विकास यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहे हैं।

कौन हैं नमित मल्होत्रा? गैराज से शुरू हुआ सफर



18 साल पहले हुए लगभग कंगाल अब बनाई 4000 करोड़ की फिल्म

भारतीय सिनेमा में जब भी किसी बड़ी फिल्म की चर्चा होती है, तो अक्सर उसके सितारों, निर्देशक और बजट पर सबसे ज्यादा ध्यान जाता है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जिनके पीछे पर्दे के आगे नजर आने वाले चेहरों से कहीं बड़ी कहानी छिपी होती है। निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म %रामायण% भी ऐसी ही एक परियोजना है। रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को बनाने की जिम्मेदारी जिस शख्स ने उठाई है, उनका नाम है नमित मल्होत्रा।

नमित आज सिर्फ एक फिल्म निर्माता नहीं, बल्कि भारतीय मूल के उन कारोबारियों में शामिल हैं, जिन्होंने विजुअल इफेक्ट्स और फिल्म निर्माण की दुनिया में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई। उनकी कंपनी ने हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों पर काम किया और उनके नेतृत्व में ष्ठह्मश्वत्र ने विजुअल इफेक्ट्स के लिए आठ ऑस्कर हासिल किए।

सात अवॉर्ड पिछले 11 वर्षों में विजुअल इफेक्ट्स के लिए मिले

सात अवॉर्ड पिछले 11 वर्षों में विजुअल इफेक्ट्स के लिए मिले हैं। कंपनी ने क्रिस्टोफर नोलन और डेनिस विलेन्यूवे जैसे हॉलीवुड के बड़े फिल्ममेकर्स के साथ भी काम किया है। लेकिन नमित की कहानी की दिलचस्प बात यह है कि उनका सफर किसी बड़े फिल्म स्टूडियो से नहीं, बल्कि मुंबई में पिता के गैराज में बने एक छोटे से एडिटिंग स्टूडियो से शुरू हुआ था। नमित मल्होत्रा का जन्म 2 अप्रैल, 1976 को मुंबई में हुआ। वह ऐसे परिवार से आते हैं, जिसकी तीन पीढ़ियां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं। उनके दादा एम.एन. मल्होत्रा भारतीय सिनेमा के जाने-माने सिनेमैटोग्राफर थे, जबकि उनके पिता नरेश मल्होत्रा फिल्म निर्माता। नरेश मल्होत्रा ने अमिताभ बच्चन की फिल्म %शहंशाह% का निर्माण किया था। इस तरह नमित के लिए फिल्मों की दुनिया कोई अनजान जगह नहीं थी। हालांकि, वह अपने परिवार की तरह पारंपरिक फिल्म निर्माण में सीधे कदम रखने के बजाय कुछ अलग करना चाहते थे। नमित की शुरुआती दिलचस्पी फिल्म निर्देशक बनने में थी। वह फिल्मों को सिर्फ कहानी और कलाकारों के नजरिये से नहीं, बल्कि उनके पीछे इस्तेमाल होने वाली तकनीक के नजरिये से भी देखते थे। 1993 में आई हॉलीवुड फिल्म %जुरासिक पार्क% ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि फिल्म देखने के बाद उनके मन में सवाल आया कि आखिर किसी ने इस तरह की दुनिया बनाने के बारे में सोचा कैसे होगा? यही वह अनुभव था, जिसने उन्हें कंप्यूटर ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स की दुनिया की ओर आकर्षित किया। फिल्मों के प्रति जुनून तो था, लेकिन उस दौर में भारत में आधुनिक डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बहुत सीमित था। नमित ने इसी कमी को अवसर के रूप में देखा। उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स की ट्रेनिंग ली और फिर अपने तीन शिक्षकों मेरजिन तवरिया, हुजेफा लोखंडवाला और प्रकाश कुरुप को अपने साथ काम करने के लिए तैयार किया। खास बात यह थी कि जिन लोगों से वह तकनीक सीख रहे थे, उन्हीं को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया।

पिता के गैराज से शुरू हुई कंपनी

साल 1995 के आसपास नमित ने अपने पिता के गैराज में एक छोटा-सा एडिटिंग सेटअप शुरू किया। इसका नाम रखा गया वीडियो वर्कशॉप। उस वक्त उनके पास न कोई बड़ा स्टूडियो था और न ही बड़ी फिल्में बनाने का बजट। उनके पास एक कंप्यूटर, कुछ तकनीकी उपकरण और कुछ नया करने का जुनून था। शुरुआत में वीडियो वर्कशॉप ने टीवी कार्यक्रमों, विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो के लिए एडिटिंग और ग्राफिक्स का काम किया। बूगी वूगी और गाथा जैसे टीवी कार्यक्रमों से भी इस स्टूडियो का नाम जुड़ा। उस समय भारतीय टेलीविजन तेजी से बदल रहा था। सैटेलाइट चैनलों का विस्तार हो रहा था और कार्यक्रमों में नए तरह के ग्राफिक्स, आकर्षक टाइटल और बेहतर एडिटिंग की मांग बढ़ रही थी।

2 साल में एक ही फिल्म क्यों करती हैं श्रद्धा कपूर

श्रद्धा ने आगे कहा, 'मुझे कभी नहीं लगता कि वुमन ओरिएंटेड या मेल ओरिएंटेड फिल्में। हमारी इंडस्ट्री को अच्छी स्टोरीज चाहिए और ऐसी स्टोरीज बनानी चाहिए। मुझे लगता है ये काफी छोटी सोच है फिल्मों को जेंडर के बेसिस पर डिवाइड करना। फिल्म की सक्सेस इन्सिडेन्टल है ना कि ये किसी के हाथ में होता है। बता दें कि ईठा महाराष्ट्र ट्रेडिशनल तमाशा और लावणी डांस फॉर्म और विठाबाई नारायणगांवकर की लाइफ पर बनी है। ईठा एक ऐसी महिला की कहानी बताती है जिन्होंने परंपराओं को तोड़ा और कई कठिनाइयों का सामना करते हुए इतिहास बनाया।

श्रद्धा को लग गई थी चोट

श्रद्धा ने डायरेक्टर लक्ष्मण को क्रेडिट दिया उन्हें ट्रेडिशनल डांस सिखाने के लिए। वह बोलीं, 'तैयारी के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पैर की मांसपेशी फट गई थी और शूट रुक गया था, लेकिन टीम काफी सपोर्टिव थी और मुझे पूरा सपोर्ट मिला। लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी दिग्गज लावणी आर्टिस्ट शकुंतली नागरकर के साथ जिन्होंने हमें ना सिर्फ डांस सिखाया बल्कि इसे समझाया। ये भी निर्देशक ने कहा कि यह फिल्म सिर्फ मशहूर तमाशा कलाकार विठाबाई की बायोपिक नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो सभी लोक कलाकारों के सफर को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह योगिराज बागुल द्वारा लिखी गई बुक तमाशा विथाबाई चा आयुष्याचा से प्रेरित है।



मोस्ट अवेटेड फिल्म फिल्म ईठा का ट्रेलर रिलीज

श्रद्धा कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म फिल्म ईठा का ट्रेलर रिलीज हो गया है जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। शुक्रवार को ट्रेलर रिलीज हुआ और इस दौरान श्रद्धा ने फिल्म को लेकर खूब बात की। इसके अलावा श्रद्धा ने यह भी बताया कि क्यों वह 2 साल में एक ही फिल्म करती हैं। ईठा फिल्म को लक्ष्मण उत्तेकर ने डायरेक्ट किया है और दिनेश विजन ने प्रोड्यूस किया है। दिनेश के साथ यह उनकी तीसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों 2 सुपरहिट फिल्म स्त्री और स्त्री 2 में काम कर चुके हैं। 2 साल में क्यों फिल्म करती हैं श्रद्धा श्रद्धा ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई रिकॉर्ड तोड़ा है या मैंने कुछ बॉक्स ऑफिस में कुछ किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे लिए मैटर करता है कि फिल्म अच्छी हो। यही वजह है कि मैं कभी-कभी 2 साल में एक पिक्चर आ जाती है मेरी।



दिलजीत कॉन्सर्ट दिल्ली में सिंगर की धूम, बारिश भी नहीं रोक पाई फैंस का जोश

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ अपने ऑरा इंडिया टूर को लेकर चर्चा में हैं। शुक्रवार को दिलजीत दोसांझ का 'ऑरा इंडिया टूर 2026' का शो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में फैंस शामिल हुए। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का ऑरा इंडिया टूर% दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू (छ्वस्ह्र) स्टेडियम में शुरू हुआ। भारी बारिश और कड़ी सुरक्षा के बीच सिंगर ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया। कॉन्सर्ट के दौरान स्टेडियम में जबरदस्त माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम को सुरक्षित तरीके से पूरा कराने के लिए आयोजन स्थल के आसपास करीब 2,000 निजी सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। दिलजीत के इस कॉन्सर्ट में शानदार स्टेज लाइटिंग, लेजर लाइट्स और आतिशबाजी ने चार चांद लगा दिए। इसके अलावा आसमान में एक बड़ा ड्रोन शो भी देखने को मिला। ड्रोन की मदद से आसमान में दिलजीत का मशहूर डायलॉग %पंजाबी आ गए ओए!% लिखा गया। इस नजारे ने वहां मौजूद फैंस का खूब ध्यान खींचा। वहीं, आसपास के इलाकों में आधी रात तक ट्रैफिक पर पाबंदियां भी लगाई गई थीं।

लाइव आकर कहा शुक्रिया

देर रात दिलजीत दोसांझ सोशल मीडिया पर लाइव भी आए। सेशन में उन्होंने दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, 'दिल्ली वालों ने इतना अच्छा इंतजाम किया। आधी रात तक मेट्रो चलाई। इतनी टाइट सिक्योरिटी दी। सबका बहुत शुक्रिया।

21 की उम्र में मां बनने पर मीरा राजपूत बोलीं काफी चैलेंजिंग था



करीना कपूर खान के चैट शो व्हट वुमन वॉन्ट का छठा सीजन चल रहा है। इस शो में कई सेलेब्स आते हैं और करीना उनसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करती हैं। अब उनके शो का जो नया एपिसोड आया है उसमें गेस्ट के तौर पर मीरा राजपूत आई हैं। मीरा, शाहिद कपूर की पत्नी हैं। इस एपिसोड के लिए सब काफी एक्साइटेड थे क्योंकि करीना, शाहिद की एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं। करीना खुद भी ये बात बोलती हैं शो के शुरुआत में कि लोग हमें साथ में देखने के लिए बेताब हैं।

मीरा ने क्या कहा मदरहुड पर

अब करीना इस दौरान मीरा से पूछती हैं कि आप 21 साल की उम्र में मां बन गई थीं तो क्या आपको कभी लगा कि कुछ और उस वक्त करना बेहतर होता तो इस पर मीरा ने जवाब दिया मुझे नहीं लगता। चाहे आपकी कोई भई उम्र हो, मदरहुड एक चैलेंज है। आपके और मेरे अलग-अलग स्टेज में बच्चे हुए हैं, लेकिन मैं श्योर हूं कि हम दोनों को चैलेंज का सामना करना पड़ा है। बच्चों की परवरिश करना काफी बड़ी बात है और उस दौरान शाहिद कपूर ने मेरी काफी मदद की। वह काफी सपोर्टिव थे।

1-13 नवंबर तक Netflix पर होगा बड़ा धमाका

एक्शन-रोमांस-थ्रिल वाली फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज



ओटीटी पर हमेशा दर्सकों को नई फिल्मों और सीरीज की रिलीज का बेसब्री से इंतजार रहता है। सब इंतजार करते हैं कि घर बैठे-बैठे वो अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज देखें। अब नवंबर का महीना आ रहा है और ये महीना ओटीटी लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला है और नेटफ्लिक्स पर तो धमाल मचने वाला है। इस महीने आपको एंटरटेनमेंट का फुल डोज मिलेगा। ओटीटी पर एक्शन से लेकर थ्रिलर, रोमांस, एक्शन और कॉमेडी फिल्में आ रही है। तो चलिए देखते हैं इस महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट। डार्क कॉमेडी और जासूसी से भरपूर थ्रिलर सीरीज ब्लैक डोव्स के दूसरे सीजन में हेलेन और सैम की स्टोरी आगे बढ़ेगी। कीरा नाइटली हेलेन और बेन विशॉ सैम किरदार से वापसी कर रहे हैं। ये फिल्म 5 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। ब्रायन टायरी हेनरी और जेनेल मोनाए की यह एनिमेटेड सीरीज वाइल्ड वेस्ट के स्टीमपंक संस्करण पर आधारित है। यह एक ऐसी काल्पनिक स्टीमपंक दुनिया के बारे में है जहां क्रूर अपराधियों, भाप से चलने वाले रोबोटों (मशीनों) और कुछ अलौकिक शक्तियों से भरी हुई है। यह 3 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। बॉक्सिंग के दिग्गज माइक टायसन अपनी लाइफ की स्टोरी इसके जरिए बताने वले हैं। इस विशेष कार्यक्रम में उन्हें खुलकर बोलने का मौका मिलता है, जिसमें उनका बेबाक और कॉमेडी अंदाज शामिल किया है है। डेनिस क्रैड इस हॉलिडे फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं। इसमें एक परिवार, प्यार और एक वफादार कुत्ते की कहानी है। जब एक आपातकालीन स्थिति के कारण गॉस परिवार अलग हो जाता है तो उनका कुत्ता विनस्टेड क्रिसमस से पहले सबको फिर से मिलाने की कोशिश करता है। अ डॉग्स परफेक्ट क्रिसमस 4 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। टेकन- नताली होलोवे में नताली हॉलोवे की स्टोरी दिखाई गई है जो मई 2005 में अरूबा में स्कूल के ग्रेजुएशन ट्रिप के दौरान लापता हो गई थीं। उनकी मां, बेथ, ने जवाब खोजने में कई साल बिताए। यह तीन-भाग वाली डॉक्यूमेंट्री गुमशुदगी से जुड़े लोगों के साक्षात्कार और बयानों के माध्यम से इस मामले को फिर से सामने लाती है। टेकन- नताली होलोवे 4 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।

पॉसिबल लव

पॉसिबल लव में नौकरी से निकाले गए एक कर्मचारी और उसकी पत्नी की मुलाकात एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और उसके पति से होती है। उनकी मुलाकात से दबी हुई इच्छाएं और निजी सवाल सामने आते हैं। यह कहानी इस बात की पड़ताल करती है कि जब लोग अपने रिश्तों और अपने द्वारा बनाए गए जीवन पर सवाल उठाना शुरू करते हैं तो क्या होता है। पॉसिबल लव 6 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

एवेडन

एवेडन में 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली फोटोग्राफरों में से एक रिचर्ड एवेडन के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालता है। मशहूर हस्तियों, राजनीतिक नेताओं और मॉडलों के पोर्ट्रेट के लिए जाने जाने वाले एवेडन ने फैशन फोटोग्राफी और लोकप्रिय संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एवेडन 11 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा।

द बॉडी

एक डांस टीम के इवेंट में गड़बड़ी हो जाती है जिससे पूरा शहर ग्रेस के बारे में जवाब खोजने में जुट जाता है। अफवाहें फैलने के साथ ही, इस बात को लेकर सवाल उठने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या था। यह रहस्य पूरे समुदाय को प्रभावित करने की धमकी देता है। फिल्म द बॉडी 11 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

द एम्प्रेस-सीजन 3

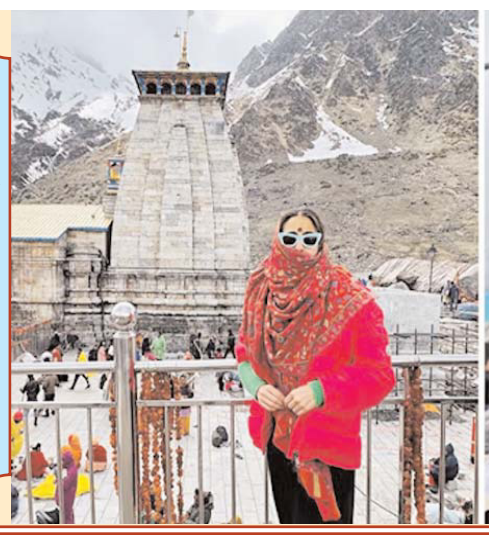
ऑस्ट्रिया की एलिजाबेथ ऐसे समय लौटती है जब शाही परिवार एक विनाशकारी युद्ध के बाद के हालातों का सामना कर रहा होता है। अपने सदमे से ग्रस्त पति फ्रांज को सहारा देने के साथ-साथ वह दरबार में बदलाव लाने के लिए भी प्रयासरत रहती है। व्यक्तिगत परेशानियां और हंगेरियन क्रांतिकारी काउंट एंड्रासी के साथ एक अप्रत्याशित संबंध उसे अपने कर्तव्यों और इच्छाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं।

मर्डर इन गैलिसिया

गैलिसिया के एक शांत कस्बे में सिलसिलेवार चोरियों और आइरीन पर हुए हिंसक हमले से दहशत फैल जाती है। अस्पताल में भर्ती आइरीन को सिविल गार्ड सार्जेंट एलियास को शक होता है कि उसके पति एनिसेटो ने ही ये सब किया है। यह क्राइम ड्रामा सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मर्डर इन गैलिसिया 13 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

सारा अली खान के केदारनाथ दौरे पर विवाद

अभिनेत्री सारा अली खान हाल ही में केदारनाथ दर्शन करने पहुंची थीं। अब उनके दौरे पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जानिए उन्होंने क्या कहा। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, %यह मौलानाओं का मामला है और उन्हें अपनी बहनों और बेटियों को रोकना चाहिए। हमने साफ कहा है कि अगर इस्लाम को लगता है कि हमारे डांडिया रास में मुस्लिम लड़के शामिल होने चाहिए, तो सिर्फ लड़के ही क्यों? उनके पूरे परिवार को इसमें शामिल क्यों नहीं होना चाहिए? उनकी बेटियां इसमें क्यों शामिल नहीं हो सकतीं? अगर बेटियां भी शामिल होती हैं, तभी इसका कोई मतलब बनता है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने आगे कहा, %सारा अली खान की बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट ने तीन दिन पहले ही फैसला दिया है कि हिंदू मंदिर पर्यटन स्थल नहीं हैं, बल्कि तीर्थस्थल हैं। अगर आपकी आस्था है तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आस्था दिखानी होगी। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।



सारा के केदारनाथ दौरे पर क्यों हुआ विवाद?

दरअसल, बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान हाल ही में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर पहुंची थीं। यहां उन्होंने दर्शन करने के साथ पूजा और आरती में भी हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्य मंदिर के अलावा पास स्थित भुकुंट भैरव मंदिर में भी पूजा-अर्चना की। सारा के इस दौरे पर बरेली के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आपत्ति जताई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना ने सारा के मंदिर जाने, पूजा करने और धार्मिक रस्मों में हिस्सा लेने को इस्लामिक कानून (शरिया) के हिसाब से नाजायज और हराम बताया था। उन्होंने अभिनेत्री से अल्लाह से माफी मांगने यानी तौबा करने की अपील भी की थी। यह पहली बार नहीं है, जब सारा अली खान के मंदिर जाने को लेकर विवाद हुआ है। साल 2018 में उनकी डेब्यू फिल्म %केदारनाथ% की कहानी को लेकर दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ रूढ़िवादी इस्लामिक विचार रखने वाले लोग उनके अलग-अलग धर्मों के धार्मिक स्थलों पर जाने को लेकर भी आलोचना करते रहे हैं।

8 साल बाद आदर्श-राधिका का ब्रेकअप की खबर

फिल्म द व्हाइट टाइगर खो गए हम कहां और तू या मैं में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता आदर्श गौरव अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। खबर है कि अभिनेता का अपनी लॉन्गटाइम पार्टनर राधिका कोलगांवकर से ब्रेकअप हो गया है। जानिए क्या है पूरा मामला। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आदर्श गौरव और मुंबई की ग्राफिक डिजाइनर राधिका कोलगांवकर इसी साल जुलाई में अलग हो गए थे। हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश भी की। उन्होंने आपसी मतभेद दूर करके एक बार फिर अपने रिश्ते को मौका देने का फैसला किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। पोर्टल से बातचीत में एक सूत्र ने बताया, दोनों ने अपने रिश्ते को बचाने और उसे बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनके अलग होने की वजहें काफी निजी हैं। आदर्श और राधिका के ब्रेकअप की खबरों को तब और हवा मिली, जब सामने आया कि दोनों अब इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि, आदर्श गौरव ने अभी तक अपने ब्रेकअप की खबरों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और न ही इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कुछ कहा है।



चक्रवात और मूसलाधार बारिश ने किसानों की सालभर की कमाई पर फेरा पानी!

खेतों में बिछी धान की फसल, श्रवण तिवारी ने सरकार से की बड़ी मांग

बिहार में प्राकृतिक आपदा से किसानों की बढ़ी मुश्किलें

तैयार धान की फसल गिरने और खेतों में जलजमाव से गहराया संकट

रेडक्रॉस बक्सर के सचिव श्रवण तिवारी ने तत्काल सर्वे, मुआवजा, फसल बीमा और विशेष राहत पैकेज देने की उठाई आवाज



बक्सर (संवाददाता)। बिहार में मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। चक्रवात, तेज आंधी और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने खेतों में पककर तैयार खड़ी धान की फसल पर संकट खड़ा कर दिया है। जिन खेतों में कुछ ही समय पहले तक किसान अपनी मेहनत से तैयार हुई सुनहरी फसल को देखकर बेहतर उपज की उम्मीद लगाए बैठे थे, वहां अब प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान की स्थिति बन गई है। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर धान की तैयार फसल खेतों में गिर गई है, वहीं लगातार बारिश से खेतों में पानी जमा होने लगा है। मौसम की इस प्रतिकूल स्थिति ने किसानों के सामने अपनी महीनों की मेहनत और तैयार उपज को सुरक्षित बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। खेती-किसानी पर निर्भर परिवारों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। किसान पूरे मौसम में खेतों की तैयारी से लेकर बुआई, सिंचाई, खाद और फसल की देखभाल तक लगातार मेहनत करते हैं। इसके बाद जब फसल पककर कटाई के लिए तैयार होती है, तब उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन चक्रवात और मूसलाधार बारिश जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों ने इस उम्मीद को झटका दिया है। खेतों में गिरी फसल और जलजमाव की समस्या ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में प्रभावित किसानों को अपनी उपज बचाने के साथ-साथ संभावित आर्थिक नुकसान की चिंता भी सताने लगी है।

किसानों की इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए रेडक्रॉस बक्सर के सचिव सह समाजसेवी श्रवण तिवारी ने बिहार सरकार से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत और सहायता उपलब्ध कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसानों ने कई महीनों तक कठिन परिश्रम करके अपनी फसल तैयार की थी। अब जब उनकी उपज घर लाने और अपनी मेहनत का परिणाम प्राप्त करने का समय आया है, तब प्राकृतिक आपदा ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। श्रवण तिवारी ने कहा कि किसानों की समस्या को गंभीरता से समझने और समय रहते आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को केवल आश्वासन देने के बजाय जमीन पर राहत पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि किसानों की मौजूदा स्थिति को प्राथमिकता देते हुए प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कराई जाए, ताकि जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है, उन्हें समय पर सहायता मिल सके।

श्रवण तिवारी ने बिहार सरकार से मांग की है कि चक्रवात, तेज आंधी और लगातार बारिश से प्रभावित इलाकों में फसल क्षति का निष्पक्ष, पारदर्शी और अविलंब सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा कि खेतों में तैयार धान सहित अन्य फसलों को हुए नुकसान का वास्तविक आकलन होना बेहद जरूरी है। सर्वे की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे प्रभावित किसानों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके और किसी भी पात्र किसान को सहायता से वंचित नहीं रहना पड़े। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल बर्बाद होने से उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। खेती में लगाई गई मेहनत और पूंजी का नुकसान होने से परिवारों के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए सरकार को नुकसान का आकलन कराने के बाद प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराना चाहिए। मुआवजा देने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसानों को संकट की इस घड़ी में तत्काल आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। रेडक्रॉस बक्सर के सचिव श्रवण तिवारी ने प्रभावित किसानों को कृषि सहायता और फसल बीमा का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुई है, उन्हें नियमानुसार उपलब्ध सहायता का लाभ जल्द मिलना चाहिए। फसल बीमा किसानों के लिए संकट के समय आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में प्रभावित किसानों को बीमा संबंधी सहायता प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित सहायता योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए, ताकि प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान झेल रहे किसानों को आर्थिक संबल मिल सके।

श्रवण तिवारी ने कहा कि किसान केवल अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए खेती नहीं करता, बल्कि पूरे देश के लिए अन्न का उत्पादन करता है। देश की खाद्य व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। खेतों में किसान की मेहनत से ही लोगों की थाली तक अनाज पहुंचता है। इसलिए जब प्राकृतिक आपदा के कारण किसान संकट में पड़ता है, तब उसके साथ खड़ा होना सरकार, प्रशासन और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है।

उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत और उनके योगदान को देखते हुए संकट के समय उन्हें तत्काल सहायता मिलनी चाहिए। प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने बिहार सरकार से अपील की कि किसानों की वर्तमान स्थिति को प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में लेकर राहत और सहायता की प्रक्रिया जल्द शुरू कराई जाए। अपनी अपील के अंत में श्रवण तिवारी ने किसानों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, 'अन्नदाता बचेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। किसान की खुशहाली ही देश की खुशहाली है।' उनका कहना है कि किसानों की आर्थिक मजबूती और खुशहाली के बिना देश की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को समय पर राहत पहुंचाना बेहद आवश्यक है।

बिहार में चक्रवात, तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के कारण धान की तैयार फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में श्रवण तिवारी ने सरकार से फसल क्षति का पारदर्शी सर्वे कराने, प्रभावित खेतों से पानी निकालने, किसानों को फसल बीमा और कृषि सहायता का लाभ दिलाने तथा विशेष राहत पैकेज घोषित करने की मांग उठाई है। अब किसानों की निगाहें सरकार और प्रशासन की ओर हैं, ताकि प्राकृतिक आपदा के कारण पैदा हुई मुश्किलों के बीच उन्हें समय पर राहत और उचित मुआवजा मिल सके।

खेतों में जलजमाव से बढ़ी परेशानी, पानी निकासी की व्यवस्था की मांग

लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों में पानी जमा होना भी किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। तेज हवाओं से फसल गिरने के साथ जलजमाव की स्थिति ने खेतों में तैयार उपज को सुरक्षित रखने की चुनौती और बढ़ा दी है। ऐसे हालात में खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करना जरूरी है, ताकि किसानों को राहत मिल सके। श्रवण तिवारी ने प्रशासन से प्रभावित कृषि क्षेत्रों में जलनिकासी की तत्काल व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन खेतों में बारिश का पानी जमा हो गया है, वहां आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक प्रयास तेज किए जाने की जरूरत है। जलजमाव की समस्या को दूर करने के साथ फसल को हुए नुकसान का भी सही आकलन किया जाना चाहिए।

किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित करने की मांग

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए श्रवण तिवारी ने बिहार सरकार से प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित करने की आवश्यकता भी जताई है। उन्होंने कहा कि धान सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने से किसानों की मेहनत और उनकी आर्थिक उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ऐसे समय में सरकार को किसानों की स्थिति को समझते हुए विशेष सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय और उनके परिवारों की आजीविका खेती पर निर्भर रहती है। फसल तैयार होने के समय प्राकृतिक आपदा का सामना करना उनके लिए बेहद कठिन परिस्थिति पैदा करता है। ऐसे में फसल क्षति का सर्वे, उचित मुआवजा, कृषि सहायता, फसल बीमा और विशेष राहत पैकेज जैसे कदम किसानों को इस संकट से उबरने में मददगार हो सकते हैं। उन्होंने बिहार सरकार से आग्रह किया कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए राहत संबंधी निर्णय जल्द लिए जाएं।

चलती ट्रेन में सीट के भीतर छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब, RPF और GRP की संयुक्त कार्रवाई में दो तस्कर गिरफ्तार



बक्सर (संवाददाता)। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बक्सर और राजकीय रेल पुलिस बक्सर की संयुक्त टीम ने शनिवार, 31 अक्टूबर को अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने गाड़ी संख्या 63230 डाउन (बक्सर-डुमरांव के बीच) में औचक जांच अभियान चलाया। इस दौरान ट्रेन की सीट के अंदर छिपाकर अवैध शराब ले जा रहे दो तस्करों को रंगे हाथों दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 8 PM ब्रांड की कुल 27 व्हिस्की की बोतलें बरामद की गईं।

जानकारी के मुताबिक, आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम शनिवार सुबह करीब 07:42 बजे ट्रेन में नियमित जांच कर रही थी। इसी दौरान दो व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों ने टीम का ध्यान खींचा। जब उनकी सीटों के आसपास सघन तलाशी ली गई, तो पैसेंजर ट्रेन की सीट में शातिर तरीके से छिपाकर रखी गई शराब की बोतलें मिल गईं। बरामद की गई अवैध शराब की कुल मात्रा 20.25 लीटर है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 12,690 रुपये आंकी गई है।

पूछताछ के दौरान पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान जयप्रकाश राय (उम्र लगभग 35 वर्ष), पुत्र - स्व. खिझा राय, निवासी - नया टोला, देदौर, थाना बख्तियारपुर, जिला पटना और सोनू राय (उम्र लगभग 25 वर्ष), पुत्र - कृष्णा राय, निवासी - देदौर, थाना बख्तियारपुर, जिला पटना के रूप में हुई है। आरपीएफ टीम ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और अवैध शराब को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए दोनों तस्करों और जब्त सामग्री को जीआरपी बक्सर को सौंप दिया गया। जीआरपी द्वारा इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है।

इस सफल छापेमारी और जांच अभियान में आरपीएफ निरीक्षक सह प्रभारी कुन्दन कुमार, उप निरीक्षक बी.एस. ओझा, सहायक उप निरीक्षक उमेश राय, सहायक उप निरीक्षक जयप्रकाश राम तथा कांस्टेबल एस.एन.एस. यादव ने सक्रिय भूमिका निभाई। रेलवे सुरक्षा बल ने स्पष्ट किया है कि रेल परिसरों और ट्रेनों के जरिए होने वाली अवैध शराब की तस्करी पर लगाम कसने के लिए निगरानी और सतर्कता अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बक्सर के बाल वैज्ञानिक दिखाएंगे प्रतिभा

बक्सर (संवाददाता)। बिहार के बेगूसराय के माउन्ट लिट्रा जी स्कूल में आयोजित तीन दिवसीय 32 वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता के अंतर्गत बक्सर जिले के प्रतिभाशाली बाल वैज्ञानिक राज्य स्तरीय आयोजन में भाग लेने के लिए बेगूसराय के लिए रवाना हो गए हैं। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में जिले के चयनित विद्यार्थी अपनी वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता, जिज्ञासा और नवाचार के माध्यम से बक्सर का प्रतिनिधित्व करेंगे। बाल वैज्ञानिकों के राज्य स्तरीय मंच तक पहुंचने से जिले के शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में उत्साह का माहौल है।

राज्य स्तरीय आयोजन में बक्सर जिले से विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इनमें +2 हाई स्कूल, सोवां के विद्यार्थी राहुल कुमार मौर्य शामिल हैं। उनके साथ शिक्षक धर्मेंद्र कुमार रमन राज्य स्तरीय आयोजन में भाग लेंगे। वहीं फाउंडेशन स्कूल, बक्सर से विकास कुशवाहा, आस्तिक कुमार पांडेय एवं आराध्य कुमारी का चयन हुआ है। इन विद्यार्थियों के साथ शिक्षक अमित कुमार भी आयोजन में शामिल होंगे। इसी क्रम में +2 राज हाई स्कूल, डुमरांव की छात्रा नियासु कुमारी भी राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बक्सर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके साथ शिक्षक प्रमोद कुमार मौजूद रहेंगे। वहीं HMS भोजपुर की छात्रा रानी कुमारी का भी चयन राज्य स्तरीय आयोजन के लिए हुआ है। उनके साथ शिक्षिका रोहिणी पाठक भाग लेंगी।

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें अपने आसपास की समस्याओं को वैज्ञानिक नजरिए से समझने के लिए प्रेरित करने वाला महत्वपूर्ण मंच है। इस आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी जिज्ञासा, कल्पनाशीलता और नए विचारों को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। राज्य स्तरीय मंच पर भागीदारी से विद्यार्थियों को अन्य जिलों के बाल वैज्ञानिकों के साथ अपने विचार साझा करने तथा नए प्रयोगों एवं नवाचारों से सीखने का अवसर भी मिलेगा।

सरदार पटेल की जयंती पर जदयू कार्यालय श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन

लेखक आशुतोष पाठक की पुस्तक 'अभ्यास' का विमोचन



बक्सर (संवाददाता)। शनिवार, 31 अक्टूबर को बक्सर जिला जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कार्यालय में भारत के प्रथम गृह मंत्री व लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।

श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश किसान नेता संजय कुमार सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने सरदार पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और अदम्य राष्ट्रभक्ति के बल पर देश की सैकड़ों रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की मजबूत नींव रखी। उनके विचार और आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा देते रहेंगे।

इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम के तहत भोजपुर जिले के दलीपपुर निवासी लेखक आशुतोष पाठक द्वारा लिखित पुस्तक 'अभ्यास' का जदयू नेताओं द्वारा औपचारिक विमोचन किया गया। उपस्थित लोगों ने पुस्तक के प्रकाशन पर लेखक को बधाई दी और साहित्य व समाज के क्षेत्र में उनके इस प्रयास की सराहना की।

कार्यक्रम में जदयू नेता व कार्यकर्ता संजय कुमार सिंह, मोहन चौधरी, जितेन्द्र कुमार सिंह, विमलेन्द्र कुमार बब्लू, प्रभु गोड़, पंकज मानसिंहका, संजय चौधरी, श्याम जी वर्मा, रामाशंकर सिंह, अधिवक्ता बिनोद सिंह, अधिवक्ता राघवेन्द्र कुमार, मार्कण्डेय पटेल, ध्रुप गुप्ता, रोहित वर्मा, दिलशाद हुसैन, मुन्ना चौरसिया, बब्लू शर्मा, नीरज पटेल, नीतीश और शशि यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी के साथी मौजूद रहे।

चौसा ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दो भाइयों को मारी टक्कर, हालत गंभीर

बक्सर (संवाददाता)। बक्सर जिले के चौसा रेलवे ओवरब्रिज पर शनिवार संध्या करीब साढ़े छह बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ओवरब्रिज पर चढ़ रही एक बाइक को सामने से आ रही अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार दो युवकों में से एक उछलकर पुल के ऊपर से नीचे सड़क पर आ गिरा, जबकि दूसरा युवक पुल पर ही गंभीर हालत में दर्द से कराहने लगा। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत पास के चौसा अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पूछताछ के दौरान घायल युवकों ने अपनी पहचान राज कुमार (30 वर्ष) और चंदन राम के रूप में बताई। दोनों सगे भाई हैं और इटाढ़ी थाना क्षेत्र के चिलहर गांव निवासी बबन राम के पुत्र हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों भाई बक्सर से चौसा के रास्ते अपने पैतृक गांव चिलहर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से वाहन लेकर फरार होने में सफल रहा। पुलिस फरार वाहन की तलाश कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बक्सर के किला मैदान में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों शिव शिष्यों ने लिया संकल्प

साहब श्री हरिंद्रानंद जी के 78वें पावन अवतरण दिवस पर वैश्विक शिव शिष्य परिवार का भव्य आध्यात्मिक आयोजन

बक्सर (संवाददाता)। भगवान शिव को गुरु मानकर उनके बताए मार्ग पर चलने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का संदेश लेकर शनिवार को बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में हजारों शिव शिष्य एकत्रित हुए। वैश्विक शिव शिष्य परिवार, बक्सर के तत्वावधान में शिव शिष्यता के जनक एवं प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के 78वें पावन अवतरण दिवस के अवसर पर भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शिव शिष्य शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का वातावरण बना रहा। आयोजन के माध्यम से लोगों को भगवान शिव को अपना गुरु बनाने, उनकी शिष्यता स्वीकार करने तथा उनके बताए मार्ग पर चलकर जीवन को सुखमय, सुंदर और सकारात्मक बनाने के लिए प्रेरित किया गया।

शिव को गुरु बनाने का संदेश बना कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों तक शिव शिष्यता के विचारों को पहुंचाना और उन्हें भगवान शिव को अपना गुरु बनाने के लिए प्रेरित करना रहा। आयोजन के दौरान 'भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं' संदेश वाले बैनर के माध्यम से शिव गुरु की शिष्यता के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि भगवान शिव चिरकाल से गुरु के पद पर आसीन हैं। उनकी शिष्यता का भाव मानव जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता, सकारात्मक सोच और शांति का विस्तार करने से जुड़ा है।



वक्ताओं ने बताया कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने स्वयं भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर शिव शिष्यता की धारा को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयासों से शिव को गुरु मानने और उनकी शिष्यता के विचार को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा मिली। इसी परंपरा के तहत उनके पावन अवतरण दिवस को देशभर में शिव शिष्यों द्वारा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिव कार्य समिति, बक्सर के अध्यक्ष एवं वैश्विक शिव शिष्य परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश कुमार दास ने शिव शिष्यता के मूल विचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की शिष्यता किसी जाति, धर्म अथवा संप्रदाय की सीमा में बंधी हुई नहीं है। समाज का कोई भी व्यक्ति भगवान शिव को अपना गुरु बना सकता है। इसके लिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी द्वारा बताए गए तीन सूत्रों का पालन किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता का उद्देश्य किसी व्यक्ति को सामाजिक बंधनों में बांधना नहीं, बल्कि उसके जीवन में सकारात्मकता, शांति और आध्यात्मिक चेतना का विस्तार करना है। भगवान शिव को गुरु मानने का भाव व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विचारों और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने लोगों को शिव शिष्यता के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान भी किया।

आयोजन में साहब श्री हरिंद्रानंद जी के जीवन और उनके आध्यात्मिक विचारों से जुड़ी शिव शिष्यता की परंपरा पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने भगवान शिव को गुरु बनाने की प्रेरणा देकर लोगों को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया। उनके बताए विचारों के माध्यम से शिव शिष्यता का संदेश समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचा है। उनके 78वें पावन अवतरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शिव शिष्यों ने श्रद्धा के साथ भाग लिया और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए किसी विशेष जाति, धर्म या सामाजिक पहचान की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव को गुरु मान सकता है। बक्सर के किला मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से हजारों शिव शिष्य पहुंचे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने आयोजन को भव्य स्वरूप प्रदान किया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक मतिउर्रहमान द्वारा अजीमाबाद प्रिंटर्स, आर. सी. एफ./105, ग्राउण्ड फ्लोर, बी. एच. कॉलोनी, भूतनाथ रोड, कंकड़बाग, पटना- 800026 बिहार से मुद्रित एवं अमला टोली, मेन रोड़, बक्सर -802101, बिहार से प्रकाशित, संपादक- मतिउर्रहमान, E-mail:- qalamlok@gmail.com, Regn. No. BIHHIN/2017/72480